सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा श्रम सम्मेलन का बहिष्कार

17 सितम्बर को देशव्यापी विरोध कार्रवाई

राष्ट्रीय अभियान समिति ने श्रम मंत्रालय द्वारा 17 व 18 सितम्बर को दिल्ली में बुलाए गये त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय अभियान समिति ने यह बहिष्कार सरकार द्वारा केन्द्रीय ट्रेड युनियनों से विचार विमर्श किए बगैर लगातार श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने तथा इस प्रकार ट्रेड युनियनों के भारी बहुमत की राय की उपेक्षा करने के विरोध-स्वरूप किया।

केन्द्रीय ट्रेड युनियनों द्वारा बार-बार प्रतिवेदन देने तथा मजदूर वर्ग के द्वारा विरोध कार्रवाइयां करने के बावजूद सरकार ने अपने एकतरफा और एक के बाद एक तानाशाही कदमों के द्वारा मजदूर वर्ग पर निष्ठुर दमन छेड़ रखा है।

राष्ट्रीय अभियान समिति के घटकों द्वारा 8-9-82 को श्रम मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल को लिखा गया पत्र, जिसमें राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के बहिष्कार के पीछे निहित कारणों को बताया गया है, इस प्रकार है :—

1. "केन्द्रीय ट्रेड युनियन मजदूर वर्ग के मसलों तथा देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर विचार करने लिए इण्डियन लेबर कनफ्रेंस बुलाने के लिए लगातार मांग करती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन 1977 में बुलाया गया था परन्तु इण्डियन लेबर कानफ्रेंस बुलाने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। 1981 में तत्कालीन श्रम मंत्री ने सभी ट्रेड युनियन केन्द्रों से विचार विमर्श करके दो बार इण्डिया लेबर कनफ्रेंस के लिए तिथि तय की परन्तु उन्हें बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया। इंटक को छोड़कर सभी केन्द्रीय ट्रेड युनियन संगठन 4 जून 1981 को बम्बई में आयोजित सम्मेलन में एक मंच पर एकत्रित हुए और मूल्य वृद्धि तथा श्रम नीतियों से सम्बन्धित अन्य मसलों पर बात चीत करने की मांग की. परन्तु सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उक्त मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आगे आई.

2. इसी बीच सरकार ने समस्त ट्रेड युनियन संगठनों तथा विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद आर्थिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में हड़तालों पर रोक लगाने के हथियार से अपने आपको लैस करते हुए एस्मा जैसे कानून का निर्माण कर लिया. सरकार ने 23 नवम्बर 1981 को संसद पर विशाल मजदूर रैली तथा 19 जनवरी 1982 की एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल की उपेक्षा कर दी और श्रमिकों से विचार-विमर्श किए बगैर औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, अस्पताल तथा अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक तथा ट्रेड युनियन (संशोधन) विधेयक आदि चार विधेयकों के माध्यम से अत्यन्त दूरगामी परिवर्तन करने का कदम उठा लिया. इन विधेयकों का उद्देश्य मजदूरों द्वारा वर्षों के संघर्षों एवं कष्टों के बाद हासिल किए गये हड़ताल एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को छीन लेना था. इन विधेयकों के अधिकांश प्राविधानों को 1978 में पेश किए गये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक से हूबहू

सार्वजनिक क्षेत्र सम्मेलन—१२-१३ अक्टूबर

ले लिया गया है जिसे इंटक सहित सभी ने नामंजूर कर दिया था. इन एकतरफा कानूनों एवं ट्रेड युनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एन० एस० ए० का दुरुपयोग करके सरकार ने श्रमिकों के साथ विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया को ही मजाक बना दिया है. हम इन श्रमिक-विरोधी कानूनों और विधेयकों को रद्द करने एवं वापस लेने की मांग करते हैं.

3. भारत सरकार व्यवस्थित रूप से सभी केन्द्रीय ट्रेड युनियनों को नजर अंदाज करती एवं इंटक को संरक्षण देती रही है. इस दौरान बनाई गई कुछ कमेटियों में इंटक प्रतिनिधियों को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया जब कि अन्य ट्रेड युनियनों को बाहर रखा गया. सरकार बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले इंटक से अकेले अथवा अलग से विचार-विमर्श करती रही है.

4. बम्बई के ढाई लाख हड़ताली कपड़ा मजदूरों के नेताओं के साथ समझौता वार्ता करने से इंकार करके सरकार ने घृणित एवं अलोकतांत्रिक वी० आई० आर० ऐक्ट को जिन्दा रखने की सोची समझी कोशिश के तहत इंटक के प्रति अपनी पक्षधरता को ही प्रदर्शित किया है. सरकार ने पिछले सभी कीतिमानों को तोड़ देने वाली बम्बई के कपड़ा मजदूरों की दीर्घकालीन हड़ताल को खतम करने के लिए कोई कोशिश न करके अपनी घोर उदासीनता का प्रदर्शन किया है. हम अविलम्ब वार्ता करके हड़ताल को खतम करने की मांग करते हैं.

5. सरकार ने बन्दियों एवं तालाबन्दियों का कोई निपटारा न करके पहले ही यह साबित कर दिया है कि उत्पादकता बढ़ाने के आह्वान का कोई महत्व नहीं है. यह सब बहुत खतरनाक हो गया है क्योंकि इससे दसियों हजार मजदूर प्रभावित हो रहे हैं जो कि बेरोजगार बनाकर प्रतिदिन सड़कों पर फेंके जा रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं. हम इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने की मांग करते हैं.

6. वेतन समझौतों में सार्वजनिक प्रतिष्ठान ब्युरो के हस्तक्षेप का समस्त ट्रेड युनियनों यहाँ तक कि स्वयं इंटक ने भी विरोध किया है. वेतन वृद्धि को 10% तक सीमित रखने और मंहगाई भत्ते को 1960 के मूल्य सूचकांक पर 1.30 रुपये प्रति प्वाइंट स्थिर करने पर जिद करने का विरोध किया गया है और सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों ने 14 सितम्बर 1979 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करके अपना विरोध प्रकट किया है. सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1960 सिरीज को रथ कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सुधारने से भी इंकार कर दिया है. अब वे और भी आगे जा चुके हैं और जहां तक संगठित क्षेत्र का सवाल है वे वेतन को उत्पादकता से जोड़ने की बात थोपने की कोशिश कर रहे हैं. इस अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण बहुत सी वेतन वार्ताएं रुक गई हैं और इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीना जा रहा है.

7. सरकार भी स्वयं केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करती रही है. एच० एम० एस० के एक अलग हुए ग्रुप को खुला संरक्षण देना उसके प्रतिनिधियों को कमेटियों में एच० एम०एस०के बराबर प्रतिनिधित्व देना गम्भीर हस्तक्षेप है. सरकार ने श्री जे० एस० दारा के ग्रुप को ये सुविधाएं न देकर अपने ऊपर लगे दोहरे मान दण्ड अपनाने के आरोपों को स्वयं ही प्रमाणित कर दिया है.

8. सरकार ने इस त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करते समय किसी भी नियम का पालन नहीं किया है. सन 1977 का सम्मेलन, जिसमें इंटक ने भी हिस्सा लिया था, समानता के आधार पर हुआ था। परन्तु इस बार प्रतिनिधित्व देने में किसी भी नियम अथवा कसौटी का पालन नहीं किया गया है.

उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि एक तरफ संगठित ट्रेड युनियन आन्दोलन कुछ जरूरी समस्यायों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने की निरन्तर कोशिश करता रहा है परन्तु दूसरी तरफ सरकार मनमाना तरीके से श्रमिकों के ऊपर कुछ निर्णय थोपती रही है और इंटक तथा अपनी नीतियों का समर्थन करने वाले अन्य संगठनों को संरक्षण देती रही है. हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हमें सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया गया है."

पत्र प्राप्त करने के बाद श्रम मंत्री ने 10 सितम्बर को केन्द्रीय ट्रेड युनियनों को अपने साथ एक बैठक के लिए बुलाया और उनसे सम्मेलन में हिस्सा लेने की अपील की तथा सीटू के महासचिव पी० राममूर्ति को एक पत्र भी लिखा. केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में शामिल न होने के अपने निर्णय को दुहराया और कहा कि चूंकि सरकार लगातार अपनी पूर्वनिर्धारित नीतियों को मजदूर वर्ग के ऊपर थोपती रही है, अतः जब तक सरकार साफ-साफ यह बयान नहीं देती है कि वह इन कानूनों में यथोचित संशोधन करने के लिए तैयार है और जब तक सम्मेलनों के माध्यम से विचार-विमर्श पूरा नहीं होता तब तक इन कानूनों और विधेयकों को स्थगित रखने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक इस सम्मेलन में हमारे हिस्सा लेने से कोई मतलब हल नहीं होगा. पी० राममूर्ति ने इसी तरह से पत्र का जवाब भी दिया.

विरोध कार्रवाइयाँ

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा विरोध-स्वरूप बहिष्कार को सम्मेलन के पहले दिन 17 सितम्बर को मजदूर वर्ग की देशव्यापी कार्रवाइयों के द्वारा जाहिर किया गया. दिल्ली में विज्ञान भवन पर जहाँ सरकार मजदूरों के खिलाफ षड़यंत्र करने के लिए मालिक-संघों, इंटक तथा उसके सहयोगी अपने मजदूर नेताओं के साथ सम्मेलन कर रही थी, लगभग 2000 मजदूरों ने पूरे दिन भर संयुक्त रूप से प्रदर्शन एवं धरने का आयोजन किया. केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के नेताओं ने पूरे दिन भर धरने में हिस्सा लिया

और मजदूरों को सम्बोधित किया. इंटक ने एक विरोधी-प्रदर्शन करके प्रदर्शनकारियों को उकसाने की कोशिश की परन्तु प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा.

इसी प्रकार से पूरे देश में जिलों और उपमण्डलीय कस्बों सहित सभी राज्यों में विशाल प्रदर्शनों जुलूसों एवं रैलियों का आयोजन किया गया. छात्रों, युवकों और महिलाओं ने सभी राज्यों में सीटू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर प्रदर्शनों का आयोजन किया और भारी संख्या में हिस्सा लिया. सम्मेलन आयोजित करने के तरीके का विरोध करते हुए ढेरों तार श्रम मंत्री को भेजे गये.

सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के इस दौर के साथ मजदूर वर्ग ने अपनी एकता को और भी मजबूत किया है तथा अगले संघर्षों के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं.

राष्ट्रीय अभियान समिति का बयान

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 21 सितम्बर को दिल्ली में सम्पन्न अपनी बैठक में केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रैलियों, प्रदर्शनों एवं धरनो के माध्यम से 17 सितम्बर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने के लिए देश भर की ट्रेड यूनियनों को बधाई दी. इन विरोध कार्रवाइयों ने एक बार फिर से यह दिखा दिया है कि देश का ट्रेड यूनियन आन्दोलन तेजी से सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है.

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बहुत बड़े बहुमत के द्वारा बहिष्कार को देखते हुए इस सम्मेलन को मुश्किल से त्रिपक्षीय अथवा प्रतिनिधिमूलक कहा जा सकता है, जैसा कि लगभग सभी समाचार-पत्रों ने स्वीकार किया है.

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन के अधिकांश निष्कर्षों को 1969 के राष्ट्रीय श्रम आयोग को सिफारिसों के श्रमिक विरोधी प्राविधानों में से लिया गया है जिन्हें आज तक किसी भी त्रिपक्षीय मंच के द्वारा पुष्ट नहीं किया गया है.

इन सिफारिशों का भारत के मजदूर वर्ग ने यहाँ तक कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरन्त बाद विरोध किया था और सरकार उन्हें आज तक लागू नहीं कर सकी. सरकार ने 17-18 सितम्बर के सम्मेलन में आयोग के उन्ही श्रमिक विरोधी एवं पुराने पड़ गये सुझावों को चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की है जिन्हें लागू करने के लिए मालिकान और इंटकी नेता लम्बे अरसे से कोशिश करते रहे हैं.

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग गठित करने के प्रस्ताव का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों की कार्य प्रणाली और उनकी गतिविधियों पर भयानक प्रतिबन्ध थोपना है और यह ट्रेड यूनियनों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार के साथ औद्योगिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाली संस्था का रूप धारण कर लेगा.

जब सबसे बड़ी सेवायोजक होते हुए सरकार ने स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में वेतनजाम थोपने के इरादे से ट्रेड यूनियनों से विचार-विमर्श किए बिना ही अपनी वेतन-नीति और रास्ता तै कर लिया है तो राष्ट्रीय वेतन नीति तै करने की बात का कोई अर्थ नहीं होगा. यह महत्वपूर्ण बात है कि वेतन निर्धारण में बी० पी० ई० के हस्तक्षेप का इंटक तक विरोध कर रहा है.

25 वर्ष बीत जाने के बावजूद 15वीं इण्डियन लेबर कानफ्रेंस द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सिद्धान्तों को आज तक लागू नहीं किया गया है.

ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए गुप्त मतदान पर विचार किए बगैर ही मालिकों और इंटक नेताओं ने सरकार को चेक आफ सिस्टम के साथ सदस्यता की जाँच करने की प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दे दी. यह सर्वज्ञात है कि मौजूदा जांच प्रक्रिया का हमारा सिद्धान्त पर आधारित विरोध जांच के लिए स्थापित मशीनरी के किसी संगठन विशेष के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैय्ये के कारण रहा है. चेक आफ के मामले में मालिकों द्वारा अपने हित में चालबाजी करने और दबाव डालने के खिलाफ सुरक्षा का कोई विश्वसनीय उपाय नहीं है.

जबकि सरकार मान्यता देने में गुप्त मतदान का विरोध कर रही है, हड़ताल की पूर्वशर्त के रूप में मतदान का सुझाव दिया जा रहा है और वह भी इस प्राविधान के साथ कि हड़ताल का निर्णय तभी हो सकता है जब कि कम से कम 60% मत इसके पक्ष में हों. इससे केवल औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में सरकार द्वारा अपनाये जाने के लिए प्रस्तावित दुहरे मानदण्डों का ही पता चलता है.

एक और भी बहुत खतरनाक निर्णय लिया गया है और वह भी इंटक के सुझाव पर, वह यह कि कोई भी यूनियन जो आचार संहिता—जो कि औद्योगिक सम्बन्ध आयोग द्वारा तैयार किया जायगा—का पालन नहीं करेगी मान्यता तक के लिए दावा कर सकने के योग्य नहीं मानी जायगी. जांच अथवा चेक आफ का सवाल तभी आएगा जब कोई यूनियन आचार संहिता की दृष्टि से योग्य समझी जायगी.

हमें पूरा यकीन है कि कोई भी यूनियन ऐसी आचार संहिता को स्वीकार नहीं करेगी. संयोग से इस संहिता की विषय वस्तु और अभी-अभी औद्योगिक विवाद कानून में जोड़े गये नये अध्याय "अनुचित श्रम व्यवहार" के प्रविधानों में क्या अंतर होगा ?

इस प्रकार राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन के विचार विमर्श ने हमारे इस आरोप को ही प्रमाणित किया है कि सरकार ने त्रिपक्षीय विचार-विमर्श को एक मजाक बना दिया है जैसा कि एन० एस० ए० और एस्मा बनाए जाने के बावजूद संसद में बहुत सारे श्रमिक विरोधी विधेयक पेश करने में देखा गया था. राष्ट्रीय अभियान समिति सम्मेलन के निर्णयों का दृढ़ता पूर्वक विरोध करती है और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ

(शेष पृष्ठ ५ पर)

जोरदार हड़ताल और पूर्ण बिहार वन्द

डेढ़ लाख पत्रकारों और गैर पर कार कर्मचारियों ने अपनी शक्तिशाली एकता का प्रदर्शन करने के लिए 3 सितम्बर को समाचार-पत्र उद्योग में अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल की. इस संघर्ष की खास विशेषता यह है कि सम्पादकों से लेकर फेरी वाले और प्रेस कर्मचारी तक सभी किसी आर्थिक मांग के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार की गारण्टी के किए संघर्ष कर रहे हैं.

यह विधेयक केन्द्र के मौन आदेशानुसार लाया गया है. इस सच्चाई का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया जब वे अमेठी में 1 सितम्बर के अपने भाषण में प्रेस कर्मचारियों के आंदोलन के खिलाफ बरस पड़ी. और इस प्रकार उन्होने संसद में सूचना और प्रसारण मंत्री के उस वक्तव्य को झूठा साबित कर दिया कि यह विधेयक विधान सभा में बिना केन्द्र की जानकारी के ही पेश किया गया था. लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करने वाली एक प्रधानमंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता । बुनियादी अधिकारों के लिए आंदोलन को व्यर्थ करार देना तो किसी अधिनायकवादी चरित्र वाले को ही शोभा देता है ।

परन्तु अब यह बात खुलकर सामने आ गई है कि न केवल इनके मंत्रीगण संसद में व्यर्थ के ब्यान दिया करते हैं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री जानबूझकर जनता में यह भ्रम फैला रही हैं कि भारवर्ष में समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वयं इंदरा गांधी के द्वारा इमरजसी के दौरान पैरों तले रौंद दी गई थी. उनकी स्वयं इन्दिरा कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों में प्रेस पर बर्बर हमले किए जा रहे हैं. इन्दिरा कांग्रेसी मंत्रियों की घृणित कारगुजारियों का पर्दाफाश करने के लिए पत्रकारों को सबक सिखवाने के लिए ही उड़िसा के एक पत्रकार की पत्नी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी. अन्तुले और गुण्डू राव ने महाराष्ट्र और करनाटक में अपने कुकर्मो का पर्दाफाश करने के लिए पत्रकारों को पागल कुत्तों की तरह खदेड़ दिया. आध्र प्रदेश में अंजैय्या ने एक पत्रकार को बाहर निकाल दिया और 19 जनवरी की हड़ताल की सफलता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी. इस प्रकार जनतंत्र की उनकी अधिनायकवादी धारणा के अनुसार उनके मंत्रियों के घोटाले, समाज-विरोधियों और डकैतों के साथ उनके सम्बन्ध, भागलपुर में बन्दियों को अंधा किया जाना, धनवाद कोयला, क्षेत्र में माफिया गिरोह का शासन, ट्रेड यूनियनों के ऊपर ठगों का नियंत्रण, पुलिस द्वारा सामूहिक वलात्कार पुलिस की हिरासत में हत्यायें, जमीदारों के द्वारा हरिजनों पर बर्बर अत्याचार, और पत्रकारों पर लाठी चार्ज आदि सभी जनतांत्रिक काम हैं, परन्तु इन सबों का प्रकाशन और इनके खिलाफ संघर्ष सभी गैरजनतांत्रिक एवं गलत हैं और उन्हें गद्दी से नीचे गिराने के राजनीतिक इरादे से प्रेरित है. प्रधानमंत्री इतनी दूरदर्शी हैं कि वह सब कुछ समझ लेती हैं, पन्रतु एक बात वह नहीं समझ पाती हैं जो कि अधिनायकशाही के उनके सपनों के कारण अवरुद्ध कर दी गई है, वह यह कि वह अपनी जनतंत्र सम्बन्धी भाषण बाजी से कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो बेवकूफ बना सकती हैं परन्तु सभी को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकती हैं.

सीटू द्वारा पत्रकारों पर बर्बर लाठी चार्ज की निन्दा

सीटू अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे तथा महासचिव एवं सांसद पी० राममूर्ति ने 22 अगस्त को निम्नांकित बयान जारी किया :

सीटू 21 अगस्त 1982 को पटना में अपना ज्ञापन देने के लिए शान्ति पूर्वक जलूस बनाकर राजपाल निवास की तरफ जा रहे पत्रकारों पर वर्बर लाठी चार्ज की जोरदारनिन्दा करती है. यह बिहार प्रेस विधेयक की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे पत्रकारों के खिलाफ बदले की कार्यवाही प्रतीत होता है.

सीटू एक बार फिर से पत्रकारों के जायज संघर्ष का समर्थन करता है और मांग करता है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगे पत्रकारों के खिलाक बदले की कार्य वाही को रोके.

तानाशाही के खिलाफ देश में वढ़ रहे लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हड़ताल की सफलता ने पूरे देश के मजदूरों और जनता के सभी हिस्सों का समर्थन हासिल कर लिया. इंदिरा कांग्रेस द्वारा संचालित कुछ अखबारों को छोड़ कर 3 सितम्बर को पूरा देश अखबार-रहित हो गया और सुबह सुबह अखबार पढ़ने के अभ्यस्त लोगों ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया. सीटू, नेशनल कम्पेन कमेटी और सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने अनोखी हड़ताल के लिए पत्रकारों को बधाई दी, जब कि इंटक को अपना ही थूक चाटना पड़ा.

पत्रकारों समाचार पत्र एवं एजेंसी कर्मचारियों को सीटू की बधाई

सीटू अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे ने 4 सितम्बर को निम्नांकित बयान जारी किया:—

भारतीय ट्रेड युनियन केन्द्र बिहार प्रेस विधेयक के माध्यम से समाचार पत्रों का मुह बन्द करने की कोशिश के खिलाफ अपना प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए 3 सितम्बर को सफक हड़ताल के लिए पत्रकारों, तथा समाचार ऐजेंसियों के कर्मचारियों को बधाई देता है.

सीटू तमीलनाडु विधेयक के साथ तुलना करके विधेयक को खुला समर्थन देने के लिए प्रधान मंत्री की तीव्र आलोचना करता है। पत्रकारों तथा समाचार उद्योग के कर्मचारियों ने बिहार प्रेस विधेयक पेश किए जाने की पृष्ठभूमि को ठीक ही समझा है. राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार, प्रतिवद्ध न्याय पालिका तथा प्रतिवद्ध समाचार पत्र और नियंत्रित प्रचार माध्यमों की वकालत की रिरंतर कोशिश की जा रही है. इसके अतिरिक्त अंतुले काण्ड से लेकर कुओ तेल समझौते तक उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा सरकार की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के घोटाले यह दिखाते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का घोर पतन किया जा रहा है. लगातार बढ़ रही तानाशाही की पृष्ठभूमि में लाया गया बिहार प्रेस विधेयक देश में जनतंत्र पर मंड़रा रहे खतरे की चेतावनी घण्टी का काम कर रहा है और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पत्रकार लोग आगे आ चुके हैं.

सीटू इस भद्दे कानून के खिलाफ संघर्ष को पूरा पूरा समर्थन देता है और इस तरह के सभी कानूनों सहित इस विधेयक को रद्द करने की मांग करता है.

बिहार बन्द

विपक्षी पार्टियों, ट्रेड युनियनों, छात्रों, नवजवानों, तथा महिला संगठनों के सम्पूर्ण लोकतांत्रिक आन्दोलन के समर्थन से 10 सितम्बर का बिहार बन्द पूर्ण रूप से सफल रहा. इन्दिरा कांग्रेस सरकार ने बन्द का विरोध करने के लिए कुछ भाड़े के लोगों को रखकर बन्द को असफल प्रमाणित करने की कोशिश की परन्तु बन्द के लिए विशाल समर्थन के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा जैसा कि विधेयक की वापसी की मांग करते हुए पटना तथा पूरे राज्य में अनगिनत जुलसों व रैकियों से प्रमाणित होता है. सभी प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थाएं बन्द रहीं, सड़कों पर यातायात बन्द रहा, दुकानों ओर चाय खानों के दरवाजे बन्द रहे तथा सिनेमा घरों ने अपने चित्रप्रदर्शन रोक दिए. सभी औद्योगिक मजदूर और आफिस कर्मचारी अपने काम पर नहीं गये. हड़ताल से पहले दिन तमाम गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र के सामने बन्द असफल होने का बयान दे देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा और इस प्रकार भोंड़ा और झूठा बयान देकर उन्होंने अपने आपको अपने ही जाल में फंसा लिया.

आंदोलन जारी है

विधेयक की वापसी के लिए आन्दोलन जारी है और इसने सम्पूर्ण देश की जनता के विभिन्न हिस्सों को अपने दायरे में खींच लिया है. समस्त विपक्षी पार्टियों, ट्रेड युनियनों किसान सभाओं, छात्रों, युवकों, महिलाओं, अध्यापकों सरकारी कर्मचारियों लेखकों, वकीलों, तथा वृद्धि जीवियों के संगठनों ने लगातार आन्दोलन शुरु कर दिया है. देश के हर गली कूचे में रैलियों, जलूसों, सम्मेलनों तथा क्रमिक अनशनों का तांता लग गया है. विधेयक को सहमति न देने के लिए प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं. पत्रकारों ने विधेयक के खिलाफ संघर्ष करने के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं के प्रश्न-काल का बहिष्कार करके, अपने मान्यतापत्रों को वापस करके, इन्दिरा कांग्रेसी मंत्रियों यहां तक कि राजस्थान में स्वयं राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार करके अपनी उदाहरणीय निर्भीकता का परिचय दिया है. इस आन्दोलन के लिए इन्दिरा प्रशासन के तानाशाही कदमों के खिलाफ तमाम लोक तांत्रिक ताकतों को हरकत में लाने तथा दीर्घकालीक दृढ़ संघर्ष छोड़ने की जरुरत है.

(पृष्ठ ३ का शेष)

और भी दृढ़ता के साथ संघर्ष चलाने के लिए मजदूर वर्ग एवं ट्रेड युनियनों का आह्वान करती है.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने देशव्यापी विरोध आन्दोलन को तेज और मजबूत करने के लिए अगला कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए 2 नवम्बर 1982 को नई दिल्ली में उद्योगवार फेडरेशनों के साथ समिति की बैठक करने का निर्णय लिया है.

न्यूनतम वेतन पर सम्मेलन

सेक्रेटरियट के निर्णयानुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की एक बैठक दि० 3 सितम्बर को दिल्ली में पी० राममूर्ति संसद सदस्य, महासचिव सीटू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.

बैठक में नृसिंह चक्रवर्ती, सुशील भट्टाचार्या, एम० पी०, चाचा शादीराम, एस० बी० भरद्वाज, जोगेन्दर शर्मा, मोहन लाल, दीवान चन्द गांधी (दिल्ली) मंगतराम पासवान (पंजाब) एस० एन० सोलंकी (हरियाणा) दौलत राम, रवि सिनहा (उ० प्र०) अमराज शर्मा (राजस्थान) तथा एस० कुमार एवं बी० के० व्यास (मध्य प्रदेश) आदि ने हिस्सा लिया.

यह देखा गया कि इन राज्यों में अकुशल मजदूरों के न्यूनतम वेतनों में काफी अन्तर मौजूद है। मौजूदा दरें इस प्रकार हैं–

राज्य	न्यूनतम वेतन	महंगाई भत्ता
हरियाणा	340/-प्रतिमाह	150 रु० प्रति प्वाइंट प्रतिमाह आधार 1972-73
पंजाब	340/-प्रतिमाह	1-00 रु० आधार 1960
दिल्ली	300/-प्रतिमाह	निल
राजस्थान	234/-प्रतिमाह	निल
मध्य प्रदेश	210/-प्रतिमाह	45 पैसे प्रति प्वाइंट प्रतिमाह, आधार 1960
उत्तर प्रदेश	208/-प्रतिमाह	महंगाई भत्ता केवल कुछ उद्योगों में ही प्रचलित है

पी० राममूर्ति ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में बताया कि इतना कम वेतन और इतना अन्तर इसलिए सम्भव हो रहा है क्योंकि जिन मजदूरों पर न्यूनतम वेतन कानून लागू होता है वे अधिकांशतः असंगठित हैं और छोटे-छोटे कारखानों में काम करते हैं। अतः हमारा प्रमुख काम उन मजदूरों के बीच जोरदार अभियान चलाना और उन्हें संगठित करना होना चाहिए. पैम्फलेट की बिक्री काफी मात्रा में की जानी चाहिये. अभियान चलाते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि मांगें ऐसी तय की जांय जिससे मजदूर यह समझ सकें कि उन्हें हासिल भी किया जा सकता है। दिल्ली में एक केन्द्रीय सम्मेलन होना चाहिए और तब उसके बाद हमें इन राज्यों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के लिये गम्भीरतापूर्वक तैयारी करनी चाहिए.

गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि सम्मेलन 31 अक्तूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाय जिसमें प्रत्येक राज्य से दो दो सौ प्रतिनिधि भेजे जायं. सम्मेलन के लिये आवश्यक तैयारी दिल्ली राज्य कमेटी करेगी. बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन पर प्रकाशित पुस्तिका की 10,000 प्रतियां बेचने का निर्णय लिया.

एन० टी० सी० मुख्यालय पर धरना

बैठक ने इन राज्यों में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की मिलों में स्थिति पर भी विचार किया. यह देखा गया कि यद्यपि अन्य सभी बातें एक समान हैं परन्तु मजदूरों को अलग अलग दर से वेतन दिया जा रहा है. दिल्ली में एन० टी० सी० मिलों के मजदूरों को टेक्सटाइल एवार्ड के अनुसार वेतन दिया जा रहा है. उ० प्र० में औद्योगिक आधार पर एक समझौता है परन्तु, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग वेतन तय किये हैं. पंजाब में इन मजदूरों को मात्र न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत निर्धारित वेतन दिया जा रहा है. राजस्थान में एन० टी० सी० द्वारा अधिग्रहीत दो मिलें औद्योगिक आधार पर सम्पन्न समझौते के मुताबिक वेतन दे रही हैं, परन्तु पिछले 5 वर्षों से वेतन एवं बोनस सम्बन्धी पिछले दावों को तय किया नहीं गया है. राहत देने के नाम पर काफी बड़ी संख्या में मजदूरों को बेरोजगार रखा जा रहा है. इसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में भी है. हर तरफ से घोर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दी गई.

मंगतराम पासला ने सूचित किया कि पंजाब में 12 सितम्बर को एन० टी० सी० मिल मजदूरों का एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें कुछ आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अपनाया जायगा. यह निर्णय किया गया कि दिल्ली हरियाणा और उ० प्र० से प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लें और इन राज्यों के लिये मांग-पत्र तैयार करें.

5 अक्तूबर 1982 को एन० टी० सी० मुख्यालय पर एक दिन का धरना आयोजित करने का निर्णय किया गया.

स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इण्डिया की तरफ से ट्रेड यूनियन इन्टरनेशनल आफ मेटल वर्कर्स के 20से24सितम्बर तक हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अर्धेन्दु दास्ती 18 सितम्बर को मास्को के लिए रवाना हो गये.

रेलवे बोर्ड द्वारा समझौतों का उल्लंघन

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने बार-बार कहा है कि रेलवे बोर्ड अपने आश्वासनों और समझौतों से लगातार पीछे हटता रहा है. सन 1967 में उन्हें काम के घण्टों में कमी करने का आश्वासन दिया गया था. परंतु उसे लागू न किए जाने के कारण उन्हें 1968 में आंदोलन शुरू करना पड़ा. एक बार फिर से उन्हें यह लिखित आश्वासन दिया गया कि सरकार काम के घण्टों में कमी करने के लिए विचार कर रही है. परतु मियां भाई ट्रिब्यूनल के समक्ष इसने काम के घण्टों में किसी प्रकार की कमी का विरोध किया और इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने क्रमिक रूप से घटौती करने का निर्णय दिया. चूंकि ट्रिब्यूनल ने आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को पार्टी मानने से इंकार कर दिया था अत: उसने ट्रिब्यूनल के निर्णयों को मानने से इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 1973 में आंदोलन हुआ. एक समझौता हुआ था जिसे 1975 में आपातकाल के दौरान पुन: तोड़ दिया गया. 1979 में काम के घण्टों को अधिकतम 10 घण्टे करने के लिए पुन: एक समझौता हुआ परंतु 1980 में रेलवे बोर्ड ने पुन: उसे भी तोड़ दिया जिसका परिणाम था जनवरी-फरवरी 1981 में पुन: एक और संघर्ष जिसे दमन के जरिये दबा दिया गया.

अब तो रेलवे बोर्ड अपने आपको इतना मजबूत समझने लगा है कि वह मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के साथ किये गये समझौतों को भी तोड़ने लगा है. पहले जे० सी० एम० की विभागीय काउंसिल में वेतनमानों को पुनर्गठित करने का एक समझौता हुआ था. इस के अतिरिक्त जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद में भी विचाराधीन कुछ मुद्दों पर अपना अन्तिम फैसला देने के लिये सरकार सहमत हो चुकी थी. पिछली जुलाई 1982 में रेलवे बोर्ड ने वेतन पुनर्गठन सम्बन्धी पूर्ववर्ती समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया और ए० आई० आर० एफ० तथा एन० एफ०आई० आर० दोनों ही के नेता बाहर निकल आए. सीटू मजदूर की इन पंक्तियों में ए० आई० आर० एफ० की वर्किंग कमेटी की वोल्टेयर में सम्पन्न बैठक में रेलवे बोर्ड की दमनात्मक नीतियों के प्रति उसे संकेत करने का समाचार प्रकाशित किया गया था. अत: सरकार की इस वादा-खिलाफी के कारण उन्हें बहिष्कार करना पड़ा.

एकजुट संघर्ष के लिए कोशिश

ए० आई० आर० एफ० नेतृत्व को जे० सी० एम० की विभागीय काउंसिल से वाक-आउट करने के बाद सांगठनिक कदम उठाने चाहिये थे. चूंकि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया अत: आल इण्डिया रेलवे इम्प्लाईज कनफेडरेशन के महासचिव तथा 12 मैन पैनल के संयुक्त संयोजक एन० एस० भंगू ने 24 अगस्त 1982 को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि:—

"जे० सी० एम० का बहिष्कार यह सिद्ध करता है कि प्रशासन रेल-मजदूरों के प्रति मात्र जुबानी हमदर्दी रखता है परंतु उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने से इंकार करता है. प्रशासन ने रेलवे में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को खत्म करने के इरादे से दमन जारी कर रखा है. ये कार्रवाइयां इस प्रकार की हैं जो कि मान्यता प्राप्त यूनियनों में भी कोई भेद नहीं करती हैं और दोनों के ही सदस्य इन प्रतिगामी श्रम नीतियों से पीड़ित हैं.

आपका जे० सी० एम० का बहिष्कार करना एक बड़ी घटना होगी और इसके परिणाम महत्वपूर्ण होंगे बशर्ते कि आप दोनो एक साथ मिलकर रेलवे में कार्यरत तमाम संगठनों-चाहे वे मान्यताप्राप्त हों अथवा गैर-मान्यता प्राप्त, कैटेगरीवाइज संगठन अथवा औद्योगिक फेडरेशन को एकजुट करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं और रेल-मजदूरों की जायज मांगों को हासिल करने लिए संघर्ष का आह्वान करें. हमें यकीन है कि यदि आप इस तरह की पहकदमी करते हैं तो तमाम रेलवे मजदूर 1974 के एन० सी० सी० आर० एस० के दौर से भी कहीं ज्यादा विश्वास के साथ आगे आएंगे.

इस दृष्टि से मैं इस पत्र की प्रति एन० एफ० आई० आर० के अध्यक्ष श्री पी० वी० आनन्दन को भेज रहा हूं जिससे कि आप दोनों ही इन प्रस्तावों पर विचार कर सकें. मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप इस संदर्भ में लिये गये निर्णयों से मुझे अवगत करा सकें."

परंतु ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० दोनों ही के नेताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया. यद्यपि 17 और 18 सितम्बर को ए० आई० आर० एफ० की बैठक हुई परंतु सदस्यों को ए० आई०आर० ई० सी० के उपरोक्त प्रस्तावों से अवगत तक नहीं कराया गया. नेताओं ने मात्र इतना बताया कि वे ए० आई० आर० ई० सी० तथा अन्यों के सम्पर्क में है.

और अन्त में नेतृत्व ने इस सवाल को अक्तूबर 1982 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन के माध्यम से रेल-कर्मचारियों के बीच ले जाने के बजाय सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया है. शायद रेलमन्त्री के परिवर्तन और उनके प्रथम बयान से कि वे रेलवे बोर्ड के पास केन्द्रित अधिकारों को कम करना चाहते हैं, इन

(शेष पृष्ट ९ पर)

कोयला मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

सात लाख कोयला मजदूर 8 नवम्बर को एक दिन की हड़ताल करेंगे. हड़ताल का आह्वान अगस्त में धनबाद में हुए कोयला मजदूरों के सम्मेलन में गठित अखिल भारतीय संघर्ष समिति के द्वारा किया गया है. कोयला मजदूर वेतन समझौतों के लिये दिये गये बी० पी० ई० के निर्देशों के खात्मे, मनमाना गठित की गई संयुक्त द्विपक्षीय समिति के खात्में, पिछले समझौतों को लागू करने तथा नये मांगपत्र में निहित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. संघर्ष समिति ने सभी कोयला यूनियनों को 18 अक्तूबर को प्रदर्शन के साथ खदान प्रशासन को हड़ताल की नोटिस देने का निर्देश दिया है. कोयला मजदूरों ने 11 सितम्बर को खदानों पर प्रदर्शनों, धरनों तथा रैलियों का आयोजन करके देशव्यापी विरोध-दिवस मनाया. संघर्ष समिति ने हड़ताल की समुचित तैयारी करने के लिये स्थानीय स्तर पर संघर्ष समितियां गठित करने का निर्णय लिया है,

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का सम्मेलन

राष्ट्रीय अभियान समिति ने सरकार की मजदूर-विरोधी एवं वेतन जाम करने की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष की तैयारी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन 12 व 13 कक्टूबर को हैदराबाद में करने का निर्णय लिया है. सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनें हिस्सा लेंगी. यह सम्मेलन कोयला, इस्पात तथा बी० एच० ई० एल० आदि बहुत से उद्योगों के वेतन समझौते में बी० पी० ई० के निर्देशों के कारण आए अवरोधों पर भी विचार करेगा. सम्मेलन में मजदूर वर्ग के संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर हाल में किए गये हमलों पर भी विचार किया जाएगा. सम्मेलन 13 अक्तूबर को एक आम सभा के साथ समाप्त होगा.

सीटू कार्यालय पर फिलिस्तीनी प्रतिनिधि का आगमन

16 से 18 सितम्बर तक सिलोगुड़ी में सम्पन्न आल इण्डिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के चौथे सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते समय फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि तोफीक सले 10 सितम्बर को सीटू के केन्द्रीय कार्यालय पर पहुचे. सीटू सचिव न्रृसिंह चक्रवर्ती तथा अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया. अमरीका समर्थित इजरायली हमले के खिलाफ पी० एल० ओ० के बहादुरीपूर्ण संघर्षों तथा भारत के मजदूर वर्ग पर इन्दिरा सरकार के तानाशाही पूर्ण हमलों के खिलाफ सीटू तथा अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा छेड़े गये संघर्ष आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

तौफीक सले ने श्रीलंका और बंगलादेश के प्रतिनिधियों के साथ प्लांटेशन मजदूरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया. उन्होंने 18 सितम्बर को बी० टी० रणदिवे तथा समर मुखर्जी संसद सदस्य के साथ खुले अधिवेशन को भी सम्बोधित किया. (सम्मेलन की रिपोर्ट अगले अंक में प्रकाशित की जायगी।)

सीटू द्वारा एच० एस० सी० एल० प्रशासन के दबाव के समक्ष झुकने से इंकार

सीटू यूनियनों ने 30 और 31 अगस्त को दिल्ली में सम्पन्न ज्वाइंट फोरम की बैठक में पहले से ही हासिल की गई अन्तरिम राहत तथा तदर्थ भुगतान को छोड़कर मंहगाई भत्ता स्वीकार करने की एच० एस० सी० एल० प्रशासन की दलील को अस्वीकार कर दिया और समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया. प्रशासन ने स्वयं अपने वायदों यहां तक कि केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री एन० डी० तिवारी के वायदों को निभाने से इंकार कर दिया तथा समझौता वार्ता को खत्म करने के इरादे से उसे लंबा खींचा. अन्त में इंटक द्वारा प्रशासन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिए जाने के कारण प्रशासन इस समझौते को सीटू आदि यूनियनों पर थोपने में सफल हो सका.

चूंकि अन्तरिम राहत वेतन सुधार की शर्त है न कि मंहगाई भत्ते के बदले में, अतः एच० एस० सी० एल० यूनियनों की समन्वय समिति (सीटू) ने वेतन सुधार के अन्तिम रूप से संपन्न होने तक बिना किसी पूर्व-शर्त के सी० पी० सी० मंहगाई भत्ते की मांग के लिए अपना संघर्ष आगे बढ़ाने का निर्णय किया है. समन्वय समिति न्यूनतम वेतन, न्यूनतम एवं अधिकतम वार्षिक वृद्धि की दरों, तथा प्रत्येक मजदूर को गारन्टी सुदा न्यूनतम नकद लाभ की मांगों के लिए भी संघर्ष करेगी.

धरने के खिलाफ भेल प्रशासन का प्रतशोध

बी० एच० ई० एल० प्रशासन ने अपने मजदूर-विरोधी चरित्र को उस समय नंगा कर दिया जब कि इसने 4 सितम्बर को मजदूर प्रतिनिधियों के मात्र डेढ़ घंटे के धरने के खिलाफ

बदले की भावना से उसी दिन होने जा रही संयुक्त समझौता समिति की बैठक को अचानक रद्द कर दिया.

सीटू, एटक, एच० एम० एस० तथा बी० एम० एस० का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 नेता दिल्ली स्थित बी०एच०ई०एल० के दफ्तर के समक्ष बैठक से पूर्व धरना दे रहे थे वे बी० एच० ई० एल० प्रशासन द्वारा बी० पी० ई० के निर्देशों के अनुसार, जिन्होंने सामूहिक सौदेबाजी को एक मजाक बना दिया है, मांग-पत्र पर सन्तोसजनक समझौता करने से इंकार करने के विरोध स्वरूप धरना दे रहे थे. इस धरने का आयोजन भेल मजदूरों की अखिल भारतीय संघर्ष समिति के निर्णय के एक हिस्से के मुताबिक किया गया था. धरने में हिस्सा लेने वालों में, एम० के पंधे भास्कर राव, (सीटू) होमी दाजी, के० एल० महेन्द्र (एटक) ओ० पी० आघी, एस० सी० शर्मा (बी० एम० एस०) वांगरु लक्ष्मण, माधव रेड्डी (भेल हैदराबाद) टी० के रंगराजन, के० एस० मुरुगसन (भेल-त्रिची) तथा बंगलौर के माइकेल बी० फर्नान्डिस आदि शामिल थे.

महिला रोजगार दिवस

भारतवर्ष में महिलाओं ने 18 अगस्त को रोजगार दिवस मनाया. महिलाओं के लिए रोजगार की मांग करते हुए इसका आह्वान आल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमेन्सएसोसिएशन तथा आल इण्डिया कोआर्डीनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन के द्वारा किया गया था. देश के बहुत से राज्यों में प्रदर्शनों, जुलूसों, धरनों तथा रैलियों के माध्यम से यह दिवस मनाया गया.

कलकत्ते में बड़े बड़े जुलूस निकाले गये जो कि स्प्लैनेड ईस्ट पर पहुंचकर विशाल सभा में बदल गये और उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री एवं सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति वसु ने सम्बोधित किया. इसी तरह से जुलूसों और रैलियों का आयोजन, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर भी किया गया जिनमें महिलाओं के विभिन्न हिस्सों ने भाग लिया. बहुत से स्थानों पर सीटू, एस० एफ० आई० तथा डी० वाई० एफ० आई० आदि संगठनों ने प्रदर्शनों की सफलता के लिए कार्य किया और बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. जनता के बीच हजारों परचे बांटे गये. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त, महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ, समान काम के लिए समान वेतन तथा एन० एस० ए०, एस्मा और अन्य श्रमिक विरोधी कानूनों को खतम करने आदि से सम्बन्धित मांगों को भी उठाया गया.

बैंक कर्मचारियों का नया संगठन

लगभग 71 हजार बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 राज्यवार संगठनों तथा 4 अखिल भारतीय बैंकवार फेडरेशनों के नेताओं ने 20 सितम्बर को दिल्ली में एक बैठक की और "बैंक इम्पलाईज फेडरेशन आफ इंडिया" नाम से एक देशव्यापी संगठन के अन्तर्गत संगठित होने का निर्णय लिया. इस संगठन का स्थापना सम्मेलन 13 से 15 अक्तूबर को कलकत्ते में सम्पन्न होगा. बैठक में शामिल 8 प्रदेशवार संगठन बिहार, प० बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, उ० प्र०, आन्ध्र प्रदेश व राजस्थान तथा विदर्भ से थे और चार बैंकवार संगठन पंजाब एण्ड सिंध बैंक यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, युनाइटेड कामर्शियल बैंक और कनारा बैंक से सम्बन्धित थे.

बैठक ने एक प्रस्ताव पास करके कर्मचारियों के हितों के खिलाफ वर्गसहयोग वादी तौर-तरीके अपनाने तथा घोर नौकरशाही एवं ट्रेड यूनियन दादागीरी के साथ अनतरिक जनवाद को खतम करने के लिए मौजूदा संगठन के नेतृत्व की तीव्र निन्दा की। इन नेताओं ने आपातकाल का समर्थन किया और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ समझौतों पर प्रशासन के साथ हस्ताक्षर किया. कर्मचारी गण वास्तव में इन नेताओं से प्रशासन तुलना में कहीं अधिक भयभीत रहने लगे थे बैठक ने वर्ग संघर्ष की नीतियों को अपनाने, प्रशासन की मजदूर विरोधी दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने तथा सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और बढ़ रही तानाशाही के खिलाफ सारे मजदूर वर्ग के साथ मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया.

(पृष्ठ सात का शेष)

नेताओं में यह नई आशा पैदा हो गई है कि यदि वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें तो उन्हें कुछ रियायत हासिल हो सकेगी.

अत: रेल-मजदूरों के एकजुट संघर्ष का सवाल भ्रमों और मान्यता को बनाये रखने तथा कुछ रियायत हासिल हासिल करने के प्रयासों के द्वारा घिर गया हैं. जबकि रेल-मजदूर अभी भी संगठित क्षेत्र के मजदूरों में सबसे कम वेतन पाने वाले मजदूर है.

सिगनल स्टाफ एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न

इण्डियन रेलवे सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक 11-12 सितम्बर को दिल्ली में सम्पन्न हुई जिसमें परिस्थितियों की समीक्षा की गई. बैठक ने लगातार जारी दमनकारी नीतियों पर भी चिन्ता व्यक्त की. बैठक ने कर्मचारियों को बिना उचित लाभ दिये हुये बड़े पैमाने पर तकनीकी आधुनिकीकरण लागू करने में वृद्धि पर गौर किया. बैठक ने इन नीतियों के प्रभाव की जानकारी हासिल करने के लिये देशव्यापी दौरे का भी कार्यक्रम तय किया.

रेल मजदूरों का धरना

मण्डल रेल प्रबन्धक मदुराई के समक्ष21 अगस्त को लगभग 800 मजदूरों ने धरना दिया और मांगपत्र सहित एक ज्ञापन पेश किया. समर मुखर्जी, संसद सदस्य ने भी रेल मन्त्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है.

कैंटीन ईम्लाईज फेडरेशन

इण्डियन रेलवे कैन्टीन इम्प्लाईज फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक 4 सितम्बर को दिल्ली में संसद सदस्य बासुदेव आचार्या की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई और मौजूदा हालात पर विचार विमर्श किया.

राजस्थान सीटू का पांचवां सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

—नृसिंह चक्रवर्ती

कोटा में 11 और 12 सितम्बर 1982 को सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी का पांचवा सम्मेलन समस्त विघटनकारी ताकतों को पराजित करके मजदूरों द्वारा स्वयं अपने वर्गीय संगठन को सम्हालने की प्रक्रिया की पूर्णाहुति के रूप में सम्पन्न हुआ। यह क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन के झण्डे को ऊँचा रखने के लिए उचित मौके पर उठ खड़े होने की साधारण मजदूरों की क्षमता का भी जोरदार प्रदर्शन था। यह सम्मेलन कोटा के मजदूरों की बहादुरी व बलिदान तथा सीटू और पार्टी (मा० क० पा०) के प्रति उनके गहरे प्यार एवं ट्रेड यूनियन जनवाद के लिए तीव्र संघर्षों के वीरतापूर्ण इतिहास में एक ओर आश्चर्यजनक घटना प्रमाणित हुआ।

पृष्ठ भूमि

पिछली जुलाई में बंगलोर में सम्पन्न वर्किंग कमेटी के निर्णयों का पालन करते हुए सेक्रेटरियट ने सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी का पुनर्गठन किया था और उसे जल्द से जल्द पांचवा राज्य सम्मेलन करने का निर्देश दिया था।

राजस्थान में सीटू को बर्बाद करने पर तुले हुए मोहन पुनमिया और उनके साथियों ने 14 और 15 सितम्बर को जयपुर में एक सम्मेलन बुला रखा था। सेक्रेटरियट ने यूनियनों को चेतावनी दी थी कि पुनमिया द्वारा बुलाए गये सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी. सचिव-परिषद् ने उक्त तिथि से पहले ही सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया जिससे कि युनियनें जान सकें और अनुसरण करने के लिए अपना रास्ता चुन सकें. अत: नई राज्य कमेटी ने दि० 22 अगस्त को सम्पन्न अपनी बैठक में 11 और 12 सितम्बर 1982 को सम्मेलन करने का निर्णय लिया.

इतने कम समय के अन्दर सम्मेलन आयोजित कर सकने की सम्भावनाओं के बारे में सन्देह व्यक्त किये गये. कोटा के साथियों ने कोटा में सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा. उनके लिए यह राजस्थान में सीटू की लाइन को आगे बढ़ाने का सवाल था. उन्होंने गर्व के साथ यह दावा किया कि चूंकि राजस्थान सीटू का प्रथम राज्य सम्मेलन कोटा में ही सम्पन्न हुआ था अत: वे इस बार भी संगठन को तमाम भटकावों और गड़बड़ियों से मुक्त करने के लिए—जो कि कुछ नेताओं के भ्रष्ट, नोकरशाहीपूर्ण और व्यक्तिवादी तौर तरीकों के कारण संगठन को जकड़ रखा है—पुन: कोटा में ही सम्मेलन करने का गर्वपूर्ण अवसर हासिल करना चाहते हैं

घटनाओं ने उनके दृढ़ विश्वास को प्रमाणित कर दिया

पुराने नेतृत्व की मुखालफत करके चुने गये कोटा के मौजूदा नेतृत्व ने सीटू को मिल रहे भारी जन समर्थन पर पूरा पूरा विश्वास रखा. मजदूरों के समूह ने नेताओं द्वारा उन पर किए गये विश्वास का यथोचित जबाब दिया. 15 दिन के थोड़े से समय के अन्दर उन्होंने सम्मेलन के लिए 60,000, रुपये एकत्रित कर दिखाया. लाल युनिफार्म में 300 स्वयं सेवकों की एक टीम गठित की गई और उसने काफी लगन और उत्साह के साथ काम किया जिसने वह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं न कि किसी मजबूरी में.

सम्मेलन के खिलाफ षड्यंत्र

उन्हें हटाए गये नेताओं के नेतृत्व में एक छोटे से ग्रुप के प्रत्याक्रमण का सामना करना पड़ा जो कि इन्दिरा कांग्रेस के समर्थकों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इंटक ने घोषणा की कि वे मजदूरों की रक्षा के लिए युनियनों का गठन करेंगे. इससे आर०एस०एस० को बढ़ावा मिला जिसने बोनस का मामला तय होने में देरी से फायदा उठाने की कोशिश की और बी० एम० एस० से माध्यम से जे० के० सिंथेटिक्स फैक्टरी के गेट पर धरना आयोजित किया। यह ज्ञात हुआ है कि 8 सितम्बर को श्री चतुर्वेदी, विधायक, की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें यह कहा गया कि पुलिस से मामले पर बातचीत हो चुकी है. इस सबका उद्देश्य था झगड़ा खड़ा करके उस नेतृत्व को फंसाना जिसे मजदूरों का विश्वास हासिल है. सन् 1971 के बोनस संघर्ष में अपनी जान देने वाले शहीदों की पुण्य स्मृति को संजोकर रखने वाले उन समस्त मजदूरों ने—जिन्होंने स्थल पर स्थाई शहीद वेदी का निर्माण करवाया है—इसे अपमानित करने का प्रयास समझा और इसका विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में निकल पड़े. बी० एम० एस० की मदद के लिए पुलिस का एक बहुत बड़ा दल वहाँ पर तैनात था. परंतु मजदूरों के गुस्से और उनकी भारी संख्या ने तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस की मदद को असम्भव कर दिया और उन्हें शीघ्र ही पीछे हटना पड़ा. परंतु उकसावा जारी रहा.

हटाए गये नेतृत्व के लोग भी मजदूरों और प्रतिनिधियों को गुमराह करने के लिए सीटू अध्यक्ष का० बी० टी० रणदिवे के नाम एक खुले पत्र के साथ सामने आए और उसे स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित करवाया.

सम्मेलन का मंच

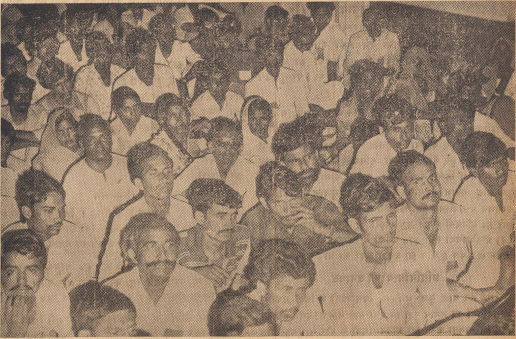

प्रतिनिधियों का वर्ग

जन-उत्साह विमुक्त

परन्तु अपनत्व की भावना के साथ काम कर रहे मजदूरों की उत्सुकता को कोई भी चीज कम नहीं कर सकी. उन्होंने अपने स्वयं के संगठन पर कब्जा कर लिया था और वे सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे. 15 दिन का बहुत थोड़ा समय होते हुए भी नवनिर्वाचित नेतृत्व ने मजदूरों का विश्वास हासिल किया और इस प्रकार जन-उत्सुकता को मुक्त करने तथा सामूहिक कार्य प्रणाली का दौर शुरू किया.

जे० के० सिंथेटिक्स मजदूर युनियन के अध्यक्ष तथा मा० क० पा० की जिला संगठन समिति के सचिव का० मांगी लाल ने जिनके सर पर आजीवन कारावास होने का खतरा लटक रहा है—संगठन के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम किया. परन्तु उन्होंने दूसरे साथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप का० अहमद अली खान, आर० के० स्वामी तथा का० जोगेश चन्द्र को क्रमशः अध्यक्ष, सचिव एवं खजांची रखते हुए स्वागत समिति का गठन किया गया. परिणामतः सम्मेलन की सफलता के लिए 60 हजार रुपये बहुत थोड़े समय के अन्दर एकत्रित किए गये और मजदूरों ने बिना किसी गुरेज के उदारतापूर्वक चन्दा दिया. नेतृत्व ने ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की स्वेच्छापूर्वक भागीदारी को सम्भव बनाने के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 10 रुपये की राशि तय की थी. मजदूरों ने भी इस कदम की प्रशंसा की और शानदार सहयोग दिया.

मजदूरों का सहयोग

नवगठित राज्य कमेटी ने 100 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर प्रतिनिधित्व तथा दर्शकों की सीमित संख्या तय कर दी थी. आने वाले प्रतिनिधियों एवं दर्शकों का अनुमान क्रमशः 250 और 100 के लगभग लगाया गया था। परन्तु इससे कहीं ज्यादा लोग उपस्थित हुए.

राजस्थान के कोने कोने से हर जाति और धर्म के मजदूरों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया. पुरुष अपनी परम्परागत राजस्थानी पगड़ी पहने हुए थे तथा महिलाएं भी परम्परागत राजस्थानी पहनावा पहने हुए थीं. तीन बड़ी युनियनों के निर्वाचित नेतृत्व ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया. परन्तु साधारण मजदूरों ने कुछ छोटे नेताओं के साथ ऐसे नेतृत्व की मुखालफत की ओर सम्मेलन में उपस्थित हुए. क्रेडेन्शियल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 84 युनियनों के 34582 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 343 प्रतिनिधियों तथा 174 दर्शकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया जिनमें से केवल 8 लोग 50 वर्ष से ऊपर की आयु के थे.

प्रतिनिधित्व की बनावट

यह सब मात्र कुछ आर्थिक उपलब्धियों के लिए एकत्रित प्रतिनिधियों का जमाव रहा हो ऐसी बात नहीं है. इसमें भयानक दमन का सामना करते हुए कठिन संघर्षों के दौर से गुजरने वाले प्रतिनिधि शामिल थे. लगभग 200 प्रतिनिधि अलग अलग समय के लिए जेलों में रह चुके थे. इनमें से 150 प्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस के मामले चल रहे हैं तथा बहुतों के खिलाफ तो 15 से भी अधिक मामले विचाराधीन हैं.

वे सभी सीटू व सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद तथा संगठन के अन्दरूनी जनवाद के झण्डे को बुलन्द करने के लिए और पुनमिया गुट की व्यक्तिवादी एवं नौकरशाहीपूर्ण गतिविधियों के खिलाफ एकत्रित हुए थे.'

शानदार स्वागत

हम लोगों के कोटा पहुंचने पर किया गया स्वागत मजदूरों के प्यार और गर्मजोशी का सूचक है. लगभग 300 कार्यकर्ता प्लेट फार्म पर उपस्थित थे. का० बी० टी० रणदिवे, का० पी० राममूर्ति और स्वयं हमें फूलमालाओं से सजी एक कार में ले जाया गया. लाल युनिफार्म पहने हुए 101 स्वयं सेवक 51 स्कूटरों तथा मोपेड गाड़ियों के साथ जुलूस के आगे आगे चल रहे थे तथा बाकी सभी स्वयं सेवक कार से पीछे एक बस में चल रहे थे. स्टेशन से लेकर हम लोगों के ठहरने की जगह सर्किट हाउस तक पूरे रास्ते में स्वयं सेवक यातायात को नियंत्रित कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मूकदर्शक की भांति खड़े हुए थे. पुनः स्कूटर-सवार 101 स्वयं सेवकों के जत्थे ने सम्मेलन हाल तक हम लोगों का मार्गदर्शन किया.

रास्ते में दो स्वागत द्वार बनाए गये थे जहां हम लोगों का मजदूरों ने स्वागत किया. एक गेट 13 सदस्यों वाली पार्टी युनिट के द्वारा बनाया गया था जोकि नौकरशाही और आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे. हम लोगों को फूल मालों से ढक दिया गया. मजदूरों की अत्यधिक उत्सुकता के कारण जुलूस में कुछ देरी हो गई और सम्मेलन की कार्यवाही अपने निश्चित समय से एक घण्टे बाद शुरू की जा सकी. सम्मेलन स्थल पर बने 'गेट' को "का० मुजफ्फर अहमद गेट" की संज्ञा दी गई थी जोकि हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे. का० बी.टी. रणदिवे ने झण्डा फहराया तथा शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया और हम सभी ने उनका अनुसरण किया.

सम्मेलन

सम्मेलन ने कार्रवाई के संचालन के लिये का० कृष्णकान्त वर्मा, पी० सी० पाण्डेय, बानो बहन, विशम्भर सहाय और शिव सरन पाण्डेय को लेकर अध्यक्ष मण्डल का चुनाव किया.

शहीदों पर प्रस्ताव तथा का० ए० बालसुब्रमण्यम मेजर जयपाल सिंह, ज्योतिर्मय बसु, भूपेश गुप्ता और सोहन सिंह जोश पर दो मिनट मौन रखकर शोक प्रस्ताव पास किये गये.

स्वागत समिति के अध्यक्ष का० अहमद अली खान ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

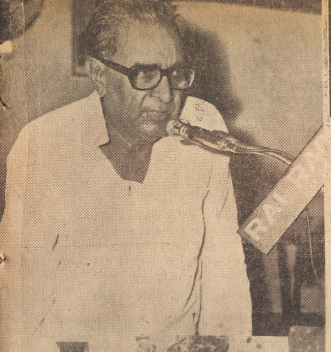

कामरेड पी० आर० और बी० टी० आर० प्रतिनिधि सम्मेलन सम्बोधित कर रहे हैं।

कामरेड बी० टी० आर० द्वारा ध्वजोत्तोलन।

केन्द्रीय नेताओं के साथ शोभायात्रा।

का० बी० टी० रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, अमरीकी साम्राजियों की उन्मादपूर्ण शस्त्र-दौड़, आणविक युद्ध के बढ़ते खतरे तथा सारी दुनिया में शान्ति के लिये बढ़ रहे शक्तिशाली आन्दोलन आदि विषयों का विस्तार से जिकर किया. इस संदर्भ में हमारे देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन की कमजोरियों का जिकर करते हुए का० रणदिवे ने विश्व ट्रेड यूनियन संघ के आह्वान पर 1 सितम्बर को युद्ध विरोधी शान्ति और एकजुटता दिवस मनाने के लिये मजदूरों को बधाई दी. उन्होंने वामपंथी एवं विपक्षी पार्टियों तथा जन-संगठनों के आह्‌वान पर 4 अक्टूबर को दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिये मजदूरों का आह्‌वान किया.

उन्होंने पिछले तीस वर्षों के दौरान शासक पार्टी द्वारा पूंजी-वादी रास्ता अपनाने के कारण लगातार गहराते आर्थिक संकट की विस्तार से चर्चा की. अब सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कर्जों के लिए जा चुकी है और इसने मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ घृणित हमला जारी कर रखा है. सरकार की वेतन नीति अपने आप में एक बहुत बड़ा आक्रमण है. बिहार प्रेस विधेयक तथा कठोर श्रम कानूनों की चर्चा करते हुए का० रणदिवे ने लगातार बढ़ रहे अधिनायक वादी खतरे के प्रति प्रतिनिधियों को सचेत किया और इसका जोरदार प्रतिरोध करने काआह्वान किया. का० रणदिवे ने सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ रही मजदूरों और जनता की एकता का स्वागत किया और 17 सितम्बर को "विरोध दिवस" मानने के लिए मजदूरों का आह्‌वान किया।

उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा था, केन्द्रीय नेतृत्व को उस सबकी पूरी पूरी जानकारी थी. उन्होंने सीटू को एक व्यक्ति का संगठन बनाये जाने के खिलाफ मजदूरों को पहले ही चेतावनी दे दी थी. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने घोषणा की कि वर्किंग कमेटी ने भ्रष्ट एवं नौकरशाही नेतृत्व को उखाड़ फेंकने तथा अपने वर्गीय संगठन की बागडोर स्वयं सम्भालने के लिए कोटा के मजदूरों को बधाई दी है. सम्मेलन की सफलता सीटू पर मजदूरों के विश्वास को प्रदर्शित करती है. उन्होंने सामूहिक कार्य प्रणाली की मांग करने तथा संगठन के अन्दर व्यक्तिवादी तथा नकोरशाहीपूर्ण कार्य प्रणाली की इजाजत न देने के लिये प्रतिनिधियों का आह्वान किया. का० रणदिवे ने प्रतिनिधियों को चेतावनी दी कि आगे आने वाले दिन बहुत ही कठिन दिन होंगे, क्योंकि अभी तक सीटू यूनियनों पर आक्रमण करने की किसी ने हिम्मत नहीं की. परंतु अब मोहन पुनमिया और उनके समर्थनों द्वारा तोड़-फोड़ किये जाने के साथ सीटू को इसकी सम्मान जनक स्थिति से हटाने के लिये आक्रमण बढ़ने की सम्भावना है. उन्होंने सीटू की नीतियों एवं संगठन की रक्षा करने के लिये प्रतिनिधियों को प्रेरित किया.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) की राजस्थान राज्य कमेटी के सचिव का० हरीराम चौहान तथा अखिल भारतीय किसान सभा की राजस्थान राज्य कमेटी के सचिव का० त्रिलोक सिंह, विधायक ने मजदूरों का अभिनन्दन किया. अन्य विभिन्न जन-संगठनों तथा सीटू की अन्य राज्य कमेटियों से बधाई संदेश प्राप्त हुए.

का० दुर्गादास शिराली ने सम्मेलन के समक्ष महासचिव की रिपोर्ट पेश की. उन्होंने बताया कि सम्मेलन की तैयारी के लिये बहुत कम समय होने के कारण लिखित रिपोर्ट की प्रतियां पूरी तरह से तैयार नहीं की जा सकीं. पिछले कुछ दिनों से राज्य कमेटी को कंकरोली स्थिति जे. के. टायर कम्पनी की घटनाओं तथा अन्य जगहों पर हस्तक्षेप करना पड़ा. उन्होंने जुबानी ही रिपोर्ट पेश की.

का० भवंरलाल बपना, रवीन्द्र शुक्ला तथा आर० एन० भटनागरको लेकर क्रेडेंशियल कमेटी तथा का० हेतराम बेनीवाल, प्रेम कृष्ण शर्मा और अब्दुल मजीद को लेकर प्रस्ताव उप समिति का गठन किया गया.

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में 32 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. पाली टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के एक प्रतिनिधि ने, जिसने यूनियन के नेतृत्व का उल्लंघन करके सम्मेलन में हिस्सा लिया, युनियन नेतृत्व की मुखालफत करने वाले मजदूरों के साथ किये जा रहे अत्याचारों की कहानी सुनायी. या तो वे प्रशासन के द्वारा नौकरी से हटा दिये गये अथवा पुनमिया-समर्थकों के द्वारा पीटे गये. जयपुर स्पिनिंग मिल के प्रतिनिधि ने, जहां के मजदूर पिछले सात माह से तालाबन्दी का सामना कर रहे हैं, बताया कि प्रशासन ने तालाबन्दी से पहले के समय का वेतन तक नहीं दिया है, मजदूरों के वेतन से काटी गई धनराशि प्रशासन जमा नहीं कर रहा है और इस प्रकार मजदूरों को ई. एस. आई. के. लाभों से वंचित किया जा रहा है और प्रशासन को दण्डित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. एक के बाद एक प्रतिनिधि ने खड़े होकर बताया कि यूनियनों की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से चलाई जा रही थी कि पुनमिया की अनुपस्थिति में युनियनों के साथ कोई भी समझौता नहीं हो पाता था. एक प्रतिनिधि ने आत्मालोचना करते हुए यह स्वीकार किया कि उसने पुनमिया गुट के साथ प्रशासन की अपवित्र मिली भगत को समझने में भूल की जिसके कारण वह स्वयं एक चुनाव के एक माह के भीतर ही दूसरे चुनाव के लिए सहमत हो गया था. रिपोर्ट पर बहुत ही जीवंत बहस हुई क्योंकि प्रतिनिधियों ने केवल पहले के दौर की घटनाओं से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया बल्कि हाल की घटनाओं पर भी विचार किया और सभी ने यह स्वीकार किया कि सम्मेलन के लिये समय की कमी के कारण समुचित तैयारियां नहीं की जा सकीं.

का० पी० राममूर्ति ने 12 सितम्बर को प्रतिनिधि सत्र को सम्बोधित किया. अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने संगठन बनाने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने यूनियन के अन्दर लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करने पर विशेष जोर दिया. का० नृसिंह चक्रवर्ती ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया और सरकार की बढ़रही तानाशाही के खिलाफ एकजुट संघर्ष की आवाज को राजस्थान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए प्रतिनिधियों का आह्वान किया.

का० बानो बहन ने राजस्थान की कामगार महिलाओं द्वारा झेली जा रही कठिनायों का जिकर किया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कामगार महिलाएं अपने आपको मजदूर आंदोलन की मुख्यधारा का का हिस्सा मानती हैं और लोगों के सामन्ती दृष्टिकोण के कारण होने वाली कठिनाइयों के बावजूद वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में सिरकत करना जारी रखेंगी.

बहुत से प्रतिनिधियों ने मजदूर आंदोलन के द्वारा किसानों तथा अन्य मेहनतकशों की समस्याओं को उठाये जाने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया.

का० दुर्गादास शिराली ने महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस का उत्तर दिया. उन्होंने आत्मालोचना के साथ सम्मेलन का तैयारियों में रह गई खामियों को स्वीकार किया. इसके साथ ही उन्होंने प्रतिनिधियों को यह आश्वासन भी दिया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान देगी और रिपोर्ट को पुनः तैयार करेगी.

उस बयान के आधार पर महासचिव की रिपोर्ट सर्वसमिति से पास कर दी गई.

तत्पश्चात का० प्रेमकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव उपसमिति द्वारा तैयार एवं पुष्ट किये गये प्रस्तावों को पढ़ा. पहला प्रस्ताव मोहन पुनमिया द्वारा बुलाये गये 14 और 15 सितम्बर के जयपुर सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से सम्बन्धित था. एक अन्य प्रस्ताव में 4 अक्तूबर को दिल्ली में हो रहे शांति मार्च में शामिल होने के लिये मजदूरों का आह्वान किया गया था. एक दूसरे प्रस्ताव में जयपुर स्पिनिंग मिल में विवाद की हल करने के लिये कोई भी कदम न उठाने के लिये सरकार को आलोचना की गई थी तथा मजदूरों की मदद करने के लिये आह्वान किया गया था. एक और प्रस्ताव के माध्यम से 17 सितम्बर को 'विरोध-दिवस' मनाने के लिये मजदूरों का आह्वान किया गया था. सम्मेलन ने एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा पत्रकारों के खिलाफ दमनात्मक कदमों की निन्दा की और बिहार प्रेस विधेयक को वापस लेने की मांग की. ये सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये.

मांगीलाल सामूहिक भभा को सम्बोधित कर रहे है : रेली का एक हिस्सा

का० हेतराम बेनीवाल ने आय-व्यय रिपोर्ट पढ़कर सुनाया का० बी० टी० रणदिवे ने भविष्य में आय-व्यय रिपोर्ट का प्रतिनिधियों के बीच बांटने के लिये कहा. इसे नोट करते हुए रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

का० दुर्गादास शिराली ने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि इसी बीच निवर्तमान राज्य कमेटी की बैठक हुई और इसने सर्व सम्मति से पदाधिकारियों तथा कमेटी सदस्यों की सूची पेश करने का निर्णय लिया है. कमेटी ने 45 सदस्यीय नई कमेटी के गठण की सिफारिश करने का निणय लिया था. प्रतिनिधियों ने एकमत से इसका समर्थन किय. तब उन्होंने पदाधिकारियों के लिए निम्नांकित नामों को प्रस्तावित किया:—

अध्यक्ष—कृष्णकांत वर्मा, उपाध्यक्ष—दुर्गादास शिराली बानो बहन शिवसरन पाण्डेय, विश्वम्भर सहाय और राधारमण गौड़, महासचिव का० प्रमकृष्ण शर्मा, संयुक्त सचिव-अनराज शर्मा, भवरलाल बपना, मांगीलाल, गनेश बेनीवाल और प्रभुलाल श्रीमाली कोषाध्यक्ष हेतराम बेनीवाल.

सात जगहों को छोड़कर जिन्हें बाद में भरा जायेगा, राज्य कमेटी के सदस्यों के नाम पढ़े गये.

प्रतिनिधियों ने एक स्वर से पदाधिकारियों और कमेटी सदस्यों की सूची की पुष्टि कर दी.

का० बी० टी० रणदिवे ने बहस का समापन करते हुए कहा कि बहस से यह ज्ञात होता है कि साथियों ने सीटू के अन्दर नौकरशाही पूर्ण व्यक्तिवादी कार्यप्रणाली के दुष्परिणामों को महसूस किया है. साथियों ने सीटू के झण्डे को बुलंद रखने के लिये उच्चस्तरीय चेतना एव बलिदान की भावना का प्रदर्शन किया है. उन्होंने सीटू को पुन: पुरानी स्थिति में लाने लिये कठिन परिश्रम करने के लिये कहा.

अध्यक्ष मण्डल की तरफ से कृष्णकांत वर्मा ने कम समय के अन्दर सम्मेलन आयोजित करने के लिये कोटो की यूनियनों और सभी साथियों को धन्यवाद दिया. उन्होने स्वयंसेवकों की प्रशसा की जिन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने क लिये लगातार तीन दिनों तक अथक प्रयास किये. उन्होंने नवनिर्वाचित राज्य कमेटी की तरफ से आश्वासन दिया कि वे लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे और इस प्रकार लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बरकरार रखेंगे. तब उन्होंने जोरदार नारों के बीच सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की.

सम्मेलन के पश्चात का० पी० राममूर्ति ने प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मेलन के निर्णयों से अवगत कराया.

ओरिएंट पावर के बिल कंपनी की सीटू यूनियन द्वारा गठित 'जन नाट्य मंच, केबिल नगर ने प्रतिनिधियों के मनोरंजन के लिये 11 सितम्बर की रात को एक प्रसिद्ध नाटक का प्रदर्शन किया. यहां पर भी एक कामगार महिला ने संस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सीटू के द्वारा महिलाओं को ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों में शामिल करके राजस्थान में कामगार महिलाओं के बीच शुरूवात की जा चुकी है.

आम सभा

कोटा के साथियों ने रैली क लिये अच्छी तैयारी की थी. 300 स्वयंसेवकों ने लाक यूनिफार्म में जुलूस का नेतृत्व किया· रैली में लगभग 5000 मजदूर शामिल हुए और जुलूस सम्मेलन स्थल से प्रारंभ होकर सबसे घनी आबादी वाले रामपुरा के इलाके से होता हुआ जे० के० सिन्थेटिक्स मजदूर यूनियन के दफ्तर के नजदीक जो कि अभी पुलिस के कब्जे में है—छावनी चौराहे पर पहुंचकर विशाल आम सभा में तब्दील हो गया. नेताओं को एक खुली जीप में ले जाया गया. रास्ते में मजदूरों द्वारा स्वागत किया किये जाने के कारण करीब 10 जगहों पर जुलूस को रुकना पड़ा. नेताओं को मालाओं से लाद दिया गया था और रास्ते भर फूलों की वर्षा होती रही. जुलूस को सभा-स्थल तक पहुंचने में तीन घंटे लगे.

एक 15 फुट ऊंचे मंच का निर्माण किया गया था जहां से नेताओं ने मजदूरों को सम्बोधित किया. सभा की सबसे खासियत यह थी कि श्रोतागण पूरी सभा के दौरान भाषण सुनते रहे. जैसे-जैसे समय बीतता गया श्रोताओं की संख्या बढ़थी गई तथा सभा रात 11 बजे तक जारी रही और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला. स्वागत समिति के सदस्य का० मांगीलाल, आर० के० स्वामी और बी० एल० चांगल, नवनिर्वाचित पदाधिकारी का० कृष्णकांत वर्मा, प्रेमकृष्ण शर्मा तथा हेतराम बेनीवाल और मा० क० पा० की राजस्थान राज्य कमेटी के सचिव का० हरि-राम चौहान ने सभा को सम्बन्धित किया. का० बी० टी० रणदिवे ने समापन भाषण दिया. श्रोताओं पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ा. सभा की समाप्ति के बाद बहुत से मजदूर उनके पास आये और बताया कि अब वे यह समझ गये हैं कि किस तरह से व्यक्तिवाद का पतन नौकरशाही और आतंकवाद के रूप में होता है और वे अब भविष्य में कभी भी सीटू यूनियनों को व्यक्तिवाद का शिकार होने की इजाजत नहीं देंगे.

नेताओं पर पुलिस झपट पड़ी

पहले से ही तैयार की गई षड़यंत्र की योजना को सम्मेलन के सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद लागू किया गया. पुलिस छिपकर प्रतीक्षा कर रही थी. 13 सितम्बर को सभी नेतागण और स्वयं सेवक कैम्पों को उजाड़ने में व्यस्त थे. बहुतेरे हफते भर के बाद थके होने के कारण आराम करने के लिए अपने घर गये थे. परन्तु आधी रात के बाद पुलिस ने का० मांगीलाल तथा अन्य नेताओं पर झपटना शुरू कर दिया ओर उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया. बी० एम० एस० द्वारा तथाकथित धारना देने की कोशिश के दौरान क्या

हुआ ?वह मूल रूप से उकसावे और गुस्सा भड़काने की बात थी जब कि नेतागण सम्मेलन की तैयारियों में लगे हुए थे. परन्तु यद्यपि वे लोग मिल गेट के आस पास कहीं भी उपस्थित नहीं थे, परन्तु फिर भी उन्हें गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया है. उनका इरादा नवनिर्वाचित नेतृत्व को जेल में बन्द करना था क्योंकि जे० के० सिन्थेटिक्स में बोनस वार्ता अभी पूरी नहीं हुई थी और वे ऐसा करके मजदूरों में अलगाव पैदा करने के लिए अशान्ति फैलाना चाहते थे.

बोनस समझौता सम्पन्न

परन्तु इधर नेता लोग भी चौकन्ने थे. नेतृत्व ने मजदूरों को आश्वासन दे रखा था कि इस बार बोनस समझौता कोटा में ही होगा न कि पिछले सालों की तरह जयपुर में जहां कि समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही उन्हें घोषित किया जाता था. अतः यद्यपि दिल्ली में कई बार वार्ता हो चुकी थी परन्तु अन्तिम समझौता दि० 16 सितम्बर को कोटा में ही गिरफ्तार लोगों को छोड़कर तीन यूनियनों के नेताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ. राज्य कमेटी की तरफ से महासचिव का० प्रेम-कृष्ण शर्मा और केन्द्र की तरफ से सचिव का० नृसिंह चक्रवर्ती उपस्थित थे. नेताओं ने पहले ही मिल कर रणनीति तैयार कर ली थी. समझौता वार्ता लगभग छः घण्टे तक चली जिसमें बोनस के अलावा बहुत सी समस्याओं को उठाया गया. मजदूर प्रतिनिधियों ने यह कहा कि यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था जबकि प्रशासन के लोग अपनी पूरी ताकत में थे और मजदूर प्रतिनिधियों ने उनके हर सवाल का यथोचित उत्तर दिया. बोनस पर अन्तिम समझौता इस प्रकार है:—

नायलान विभाग के लिए 20% बोनस तथा 685/-एक्सग्रेशिया, एस० एस० एफ० विभाग के लिए-20% बोनस तथा 765/-एक्सग्रेसिया, टायर कार्ड विभाग के लिए-20% बोनस तथा 820/-एक्सग्रेसिया.

एक्रेलिक डिवीजन के नाम से एक चौथा विभाग 1980 से शुरू किया गया है, अतः बोनस कानून के अन्तर्गत उन्हें कोई बोनस नहीं मिलना था । पिछले वर्ष बोनस समझौतों के समय उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया था. इस वर्ष नेताओं ने यह दृढ़ निश्चय कर रखा था कि आगामी त्योंहारों के दौरान खर्चों को निपटने के लिए मजदूरों को आवश्य कुछ न कुछ राशि मिलनी चाहिए. अन्त में युनियनों ने 250/-प्रति मजदूर हासिल कर ही लिया.

उद्योग की स्थिति को देखते हुए मात्र आर्थिक लाभ की नजर से यह पिछले वर्ष के समझौते से बेहतर है । इस समझौते के लिए प्रशासन को 30 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी जिसे सीटू द्वारा दृढ़ रुख अपनाने के कारण इसी समझौते में सुरक्षित कर लिया गया है. युनियन के नेताओं ने 16 सितम्बर की शाम को हुई एक बैठक में सारे तथ्य युनियन कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा जिसमें लगभग 400 मजदूरों ने हिस्सा लिया. मजदूरों ने सवाल किए. कुछ ने कहा कि वृद्धि एक समान होनी चाहिए थी. और नेताओं ने बताया कि पहले के समझौतों में नायलान डिविजन में धनराशि की कटौती की स्वीकृति बराबर बोनस के रास्ते में आड़े आ रही थी. एक्रेलिक विभाग के मजदूरों ने इतनी कम धनराशि के लिए अप्रसन्नता जाहिर की. परन्तु उन्हें यह बताया गया कि पहली बार एस० एस० एफ० तथा टायर कार्ड डिविजनों में भी बहुत कम राशि से ही शुरूआत हुई थी. कुछ तत्वों ने इस विभाग के मजदूरों को भड़काने की कोशिश की परन्तु वह सफल नहीं हो सके.

राजस्थान के मजदूर सीटू की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं

राजस्थान के मजदूर तोड़ फोड़ और पुलिस-दमन के बावजूद निर्भय होकर आगे बढ़ रहे हैं. मौके का फायदा उठाने की ताकत में लगे हुए इंटक और बी० एम० एस० की कोशिशों को भी उन्हें नाकाम करना है. राजस्थान सीटू के पांचवें सम्मेलन ने राजस्थान में क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन विकसित करने के लिए नींव डाल दी है. नवनिर्वाचित नेतृत्व ने केन्द्रीय नेताओं से जल्दी से जल्दी कक्षाएं चलाने का आग्रह किया जिससे कि जुझारु कार्यकर्त्ता स्वतंत्र रूप से ट्रेड युनियन सम्बन्धी समस्याओं से निपट सकें और इसके साथ ही साथ वे ट्रेड युनियन चेतना को समाजवादी चेतना में तब्दील करने के काबिल भी हो सकें.

मजदूरों के बीच पहले ही खबर फैल रही थी. जयपुर में 14-9-82 को कमानी उद्योग के गेट पर तथा राजस्थान ट्रान्सफार्मर के विश्वकर्मा केन्द्र पर राज्य सीटू के नवनिर्वाचित नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया. यह स्वभाविक है कि पुनमिया के समर्थनों ने पुनविचार करना शुरू कर दिया है. □

सम्पादक मंडल
बी० टी० रणदिवे अध्यक्ष
पी० राममूर्ति मनोरंजन राय
नीरेन घोष सुधीन कुमार
एम० के० पंधे (सम्पादक)

युद्ध के खिलाफ, शांति के पक्ष में

1 सितम्बर सारी दुनिया में मनाया गया

सारी दुनिया के मजदूर जब कि अभी दिमित्रोव शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उन्होंने महान अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा नेता के निम्नांकित शब्दों को याद किया जो कि उन्होंने उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के खतरे के खिलाफ चेतावनी देते हुए कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय की सातवीं कांग्रेस में 1935 में कहा था : "इस वक्त इतिहास ने विश्व सर्वहारा के समक्ष फासिज्म की बर्बरता तथा नये साम्राज्यवादी कत्लेआम – जिसकी वह तैयारी कर रहा है—की विभीषिका से मानव जाति की रक्षा करने का महान कर्त्तव्य उपस्थित किया है।" आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी दिमित्रोव के उपरोक्त शब्दों की सच्चाई को प्रमाणित करती हैं. सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की अमरीकी सनक ने सोवियत संघ एवं समाजवादी खेमे को अपना मुख्य निशाना बनाते हुए सारी दुनिया को नाभिकीय विध्वंश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. इसके साथ ही अमरीका के समर्थन से सीधे काम कर रहे फासिस्ट यहूदीवादी बेगिन ने फासिस्ट हिटलर के बाद फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन तथा लेबनानी राष्ट्रीय आन्दोलन को खतम करने के इरादे से मानव जाति का बर्बर संहार करना शुरू कर दिया है.

इस वर्ष विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलन ने, परिस्थितियों की माँग को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुवात के दिन 1 सितम्बर 1939 को पहली बार याद किया और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलन्द रखते हुए युद्ध के खिलाफ तथा शान्ति के पक्ष में अपनी आवाज बुलन्द की.

भारतवर्ष में मजदूर वर्ग ने देश के सभी कोनों से इसका पालन करके शुरुवात की.

दिल्ली

ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज I मे सीटू ने लगभग 500 मजदूरों का जुलूस निकाला और सभा की. फेज II में भी एटक के साथ जुलूस एवं रैली का आयोजन किया गया. नरैना औद्योगिक क्षेत्र में एक और जुलूस और रैली का आयोजन किया गया. यहाँ पर इसके पूर्व 28 और 30 अगस्त को भी दो जुलूस निकाले गये. सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने युद्ध के खिलाफ अभियान में 30,000 पर्चे बांटे. शाम को एक सयुक्त सभा को पी० राममूर्ति (सीटू) इन्द्रजीत गुप्ता (एटक) और सुशील भट्टाचार्या (यु० टी० यु० सी०) ने सम्बोधित किया.

उत्तर प्रदेश

राज्य कमेटी के आह्वान पर कानपुर एवं गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों तथा जिला मुख्यालयों पर शान्ति जुलूसों और रैलियों का आयोजन किया गया. कई स्थानों पर एटक तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रैलियों का आयोजन किया गया.

हरियाणा

औद्योगिक क्षेत्रों में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया. फरीदाबाद में एक केन्द्रीय जिला स्तर की रैली की गई जिसे दिल्ली प्रदेश सीटू के अध्यक्ष चाचा सादीराम तथा अन्य लोगों ने सम्बोधित किया.

बिहार

पटना में जोरदार बारिस के बावजूद विभिन्न युनियनों ने जुलूस निकाला और पी एण्ड टी मनोरंजन क्लब में रैली का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता बिहार राज्य सीटू के महासचिव चण्डीप्रसाद ने की. बी० एस-एस० आर० युनियन ने शहर के चार केन्द्रों पर युद्ध की तवाही से सम्बन्धित पोस्टरों का प्रदर्शन किया. दो हजार पोस्टर चिपकाये गये और 5000 पर्चे बाँटे गये.

जमशेदपुर

पुलिस ने शान्ति जुलूस पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया और रीगन का पुतला छीन लिया. सीटू-नेता नरेन्द्र मिश्र तथा कुछ पत्रकारों सहित बहुत से लोग घायल हो गये. बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गये. फिर भी मजदूरों ने रीगन का एक दूसरा पुतला तैयार किया और जंगबाजी के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए उसे जलाया. छोटे-छोटे कस्बों सहित राज्य के सभी हिस्सों में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किए गये. कई स्थानों पर मशाल जुलूस निकाले गये.

आसाम-त्रिपुरा

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी हिस्सों में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया. युद्ध के खिलाफ पारित प्रस्तावों की प्रतियां प्रधान मंत्री को भेजी गयीं.

उड़ीसा

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विभिन्न युनियनों के द्वारा अलग अलग एवं एक साथ मिलकर सभाओं रैलियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा प्रस्ताव पास किये गये.

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता में अमरीकी सूचना सेवा के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सीटू के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल, एम० पी०, ने की. रैली का आयोजन सीटू, एटक, टी० यु० सी० सी०, एच० एम० पी०, 12 जुलाई कमेटी तथा अन्य संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. रैली ने 23 सितम्बर को कलकत्ता में एक राज्यस्तरीय रैली करने का निर्णय लिया. राज्य के हर कोने में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया.

महाराष्ट्र

बम्बई में औद्योगिक क्षेत्रों तथा उपनगरों से बहुत से जुलूस निकाले गये और सभी आजाद मैदान में एकत्रित हुए. वहां से जुलूस अमरीकी सूचना सेवा पर पहुंचा और वहाँ पर विशाल रैली की गई. मजदूरों ने सीटू द्वारा छापे गये बिल्ले लगा रखे थे जिन पर लिखा था "युद्ध नहीं, शान्ति चाहिए." सीटू ने रैली से पहले तैयारी के लिए कई सभाएं कीं, पोस्टर चिपकाए और परचे बांटे.

गोवा

सीटू की गोवा राज्य कमेटी ने अन्य यूनियनों के साथ मिलकर प्रचार अभियान और सभाओं का आयोजन किया तथा युद्ध की तैयारियां करने और पी० एल० ओ० के खिलाफ बर्बर यहूदीवादी इजरायली हमले को समर्थन देने के लिए अमरीका की निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास किया. प्रस्ताव की प्रतियां प्रधानमंत्री और गोवा के मुख्य मंत्री को भेजी गईं.

मध्य प्रदेश

इन्दौर में संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल ने गांधी हाल से एक विशाल जुलूस निकाला जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ राजवाड़ा जनता चौक पर पहुंच कर विशाल रैली में बदल गया. रैली को कल्यान जैन, वाला जी टोकेकर, जगन्नाथ भारती तथा अन्य लोगों ने सम्बोधित किया.

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रदर्शन-सभा को सीटू के पी० के० मोइत्रा तथा एटक के ततइया ने सम्बोधित किया. बिलासपुर में सुरकद्दार में कोयला श्रमिक संघ (सीटू) ने एक विशाल रैली का आयोजन किया. मध्य प्रदेश मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव एसोसिएशन ने शास्त्री चौक, राजपुर, से एक जुलूस निकाला तथा गांधी चौक पर सभा की एवं जनता के बीच परचे बांटे.

कर्नाटक

बंगलौर में सीटू के तत्वावधान में मैसूर बैंक स्क्वायर से एक जुलूस निकाला गया और राजभवन पहुँचकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया. मंगलूर में 3000 मजदूरों की एक रैली को सीटू के पी० रामचन्द्र राव और एटक के बी० वी० ककिलैय्या ने सम्बोधित किया. इसी तरह से रैलियों और सभाओं का आयोजन उदीपी, कुन्दापुरा, भारत गोल्ड माइन्सः एम० एस० के मिल वर्कर्स यूनियन, (सीटू) कर्नाटक थोटा कर्मिक संघ, (सीटू) बीजापुर, कुभगल, तिप्तूर, सौंदत्ती, सिमोगा, रायचूर तथा अन्य जगहों पर भी किया गया.

आंध्र प्रदेश

सीटू और एटक के तत्वावधान में विजय बाड़ा, विशाखापटनम, गुण्टूर, नेल्लोर, कुर्नूल, राजाभुन्दरी, पालाकोल, एलुए मछली पटनम, तेनाली, खम्मम, हैदराबाद चिराला, चेडाकाकनी, वयूर, वारंगल, तनुकु, तथा अन्य जगहों पर विशाल प्रदर्शनों, संयुक्त रैलियों तथा साइकिल जुलूसों का आयोजन किया गया.

सीटू द्वारा शान्ति मार्च पर पुलिस लाठी चार्ज की निन्दा

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र के अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे ने 4 सितम्बर को निम्नांकित बयान जारी किया :

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र 1 सितम्बर 1982 को युद्धविरोधी शान्ति एवं एकजुटता दिवस मनाने के लिए (बिस्टूपुर) जमशेदपुर में एकत्रित मजदूरों के ऊपर पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक लाठी वर्षा किये जाने की निन्दा करता है. यह कार्यक्रम विश्व ट्रेड यूनियन संघ के आह्वान पर सारी दुनिया में तथा सीटू व एटक तथा बैंक और एल० आई० सी० फेडरेशनों के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मनाया गया. प्रदर्शनकारी अमरीका द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों की निन्दा करने तथा पी० एल० ओ० के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए रीगन और बेगिन के पुतलों के साथ एकत्रित हुए थे. पुलिस ने बिना कोई सूचना दिये अचानक लाठी वर्षाना शुरू कर दिया जिसमें 12 लोग घायल हो गये और धारा 144 तोड़ने के नाम पर सभी को गिरफ्तार कर लिया.

यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जमशेदपुर में पुलिस ने टाटाओं के निर्देश पर इंटक के अतिरिक्त सभी ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को खतम करने के लिये धारा 144 थोप रखा है. पुलिस ने लाठी चार्ज करके और यहाँ तक कि नाभिकीय युद्ध, न्यूट्रान बम के खिलाफ तथा शान्ति के लिए नारे लगाने वालों पर झपट कर केवल टाटा प्रशासन के प्रति अपनी दासता का ही प्रदर्शन किया है.

सीटू माँग करती है कि बिहार सरकार इस ज्यादती के लिये जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें और धारा 144 को वापस ले जिससे कि साधारण ट्रेड यूनियन कारंवाइयों को जारी रखा जा सके.

तमिलनाडु

सूचना के अनुसार, सभी औद्योगिक क्षेत्रों और जिलों में प्रदर्शनों एवं रैलियों का आयोजन किया गया. विभिन्न यूनियनों ने रैलियों में हिस्से लिए, परचे बांटे तथा पोस्टर चिपकाए. मद्रास में अमरीकी वाणिज्य दूतावास के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया जिसमें सीटू तथा एटक दोनों ने हिस्सा लिया.

केरल

एक सितम्बर को ओनम की छुट्टी होने के कारण केरल में शान्ति दिवस 9 सितम्बर को मनाया गया. त्रिवेन्द्रम में जन चेतना अभियान के तहत 1 सितम्बर से कई दिनों के लिए युद्धविरोधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. ओनम त्योहार के लिए शहर आने वाले हजारों लोगों ने प्रदर्शनी देखा. राज्य के सभी हिस्सों में प्रदर्शनों, रैलियों, जुलूसों और जन सभाओं का आयोजन किया गया.

सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएसनों युनियनों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक मजदूरों, मध्यमवर्गीय कर्मचारियों महिला संगठनों, छात्रों व युवकों, के संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष का मजदूर आन्दोलन लगातार बढ़ रहे युद्ध के खतरे के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्यधारा में समाहित हो रहा है और वे मानव जाति के मुख्य शत्रु अमरीकी साम्राजियों को पहचानने लगे हैं. इन प्रदर्शनों की सबसे खासियत थी बहुत बड़ी संख्या में विशेष रूप से छात्रों और युवकों की भागीदारी. एस० एफ० आई० तथा डी० वाई० एफ० आई० की इकाइयों ने हर जगह पर प्रदर्शनों को सफल बनाने, अन्धराष्ट्रवादी अमरीका के खिलाफ लगातार संघर्ष करने अमरीका समर्थित यहूदीवाद की निन्दा करने शान्ति, समाजवाद और जनतंत्र की रक्षा के लिए मजदूरों और तमाम जनता को उत्साहित करने के लिए सीटू के साथ मिलकर कड़ा परिश्रम किया.

विदेशों में शान्ति दिवस

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दुनिया के हर कोने में प्रदर्शन किएगये. विश्व ट्रेड युनियन संघ के आह्वान का अनुपाल न केवल मजदूर वर्गों ने ही नहीं किया बल्कि पूंजीवादी दुनिया के तमाम शहरों में अमरीकी रीगन प्रशासन की युद्ध नीतियों की निन्दा करने के लिए साधारण जनता भी सड़कों पर निकल पड़ी. समाजवादी देशों में भी अमरीकी साम्राज्यवाद, यहूदीवाद और फासीवाद की निन्दा करते हुए विशाल प्रदर्शन किए गये.

लेबनान में इजरायली नरसंहार

सारी दुनिया में प्रदर्शनों में बेगिन के अपराधी कुकृत्यों के खिलाफ, जिन्हें किसी भी मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तीव्र घृणा और गुस्से का इजहार किया गया. लेबनान में जिस पाशविक सनक के साथ निहत्थे नागरिकों, महिलाओं बच्चों और वृद्धों का कत्ले आम किया गया उससे पी० एल० ओ० के खिलाफ यहूदीवादियों की बर्बर प्रतिहिंसा का ही पता चलता है और यह हिटलर के नरसंहार को भी मात कर देता है. बहुत से स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने एक साथ रीगन और बेगिन के पुतले जलाये. प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की एक मात्र साम्राज्यवाद-विरोधी ताकत फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का मौजूदा समय में मानव जाति के सबसे खतरनाक शत्रु—अमरीकी साम्राज्यवाद और यहूदीवादी गठजोड़ के खिलाफ इसके अदम्य संघर्ष के लिए अभिनंदन किया.

इसराइल द्वारा फिलिस्तीनी नरसंहार की सीटू द्वारा निन्दा

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र के महासचिव व संसद सदस्य पी० रामूर्ति ने 20 सितम्बर को निम्नांकित बयान जारी किया :—

सीटू 18 सितम्बर को पश्चिम बेरुत के साबरा कैम्प में यहूदीवादी इसराइली सैनिकों तथा दक्षिणपंथी फलांगीवादी अर्धसैनिकों द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों की तरह जघन्य नरसंहार करने की तीव्र निन्दा करता है. समाचार पत्रों में छपी खबरों से ज्ञात हुआ है कि साबरा कैम्प से बाहर जाने के सभी रास्ते बन्द कर दिए गये थे और वृद्धों, महिलाओं, तथा बच्चों सहित सभी गैर सैनिक जनता को निर्दयतापूर्वक टैंकों तथा बख्तर बन्द गाड़ियों से उड़ा दिया गया. समाचारों से यह भी ज्ञात हुआ है कि बच निकली महिलाओं के साथ उन्मादी सैनिकों ने बलात्कार किए. इस नाजी किस्म की सामूहिक हत्या की विभीषिका ने स्वभावतः तमाम विश्व के जनवादी मतानुयायियों यहां तक कि स्वयं इसराइली नागरिकों में घृणा पैदा कर दी हैं. कोई भी शब्दावली ऐसी नहीं है जिसमें इस घृणित काम की निन्दा की जा सके जिसके लिए इसराइली फौजें तथा यहूदीवादी शासक दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं.

सीटू पश्चिम एशिया पर नियंत्रण हासिल करने की इसराइली योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अमरीका के रीगन प्रशासन की निन्दा करती है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई हैं.

सीटू संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसरायल पर रोक लगाने तथा जघन्य हत्या काण्ड के लिए जिम्मेदार लोगों पर उनके युद्ध-अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग करता है. सीटू इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से दृढ़ स्थिति अपनाने की मांग करता है. सीटू देश की तमाम शान्ति प्रेमी जनता से अपनी जोरदार आवाज उठाने की मांग करता है जिससे कि भारत सरकार को साफ-साफ रवैया अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके.

मजदूर वर्ग को यह अवश्य समझना चाहिए कि फासीवाद, साम्राज्यवाद, यहूदीवाद अथवा युद्ध कभी भी स्थाई नहीं हो सकते हैं. हिटलर सोवियत युनियन के हाथों समाप्त हुआ और अमरीका को वियतनाम में बुरी तरह पराजित होना पड़ा. उन्हें खतम किया जा सकता है और खतम किया जायगा. एक तिहाई दुनिया पहले ही समाजवादी खेमें में आ चुकी है. संयुक्त संघर्षों और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलंद रखते हुए समाजवाद की रक्षा की जिम्मेदारी मजदूर वर्ग पर आती है. 1 सितम्बर अमरीकी साम्राज्यवाद के लिए चेतावनी की घण्टी था. भारत वर्ष में 4 मार्च के शान्ति मार्च के माध्यम से जनता के और बहुत बड़े हिस्से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के दायरे में आएंगे.

राज्यों के समाचार

मध्य प्रदेश

म० प्र० सीटू की बैठक

सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी ने 14 व 15 अगस्त को मोतीलाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न अपनी बैठक में मजदूरों के विभिन्न संघर्षों तथा सरकार की दमनकारी नीतियों की समीक्षा की. वरवेली मैंग्नीज माइन्स के मजदूरों पर, जो कि मात्र अपनी यूनियन के सेक्रेटरी के खिलाफ निलम्बन आदेश की वापसी की मांग कर रहे थे, बिना किसी उकसावे के गोली चलाने के बाद अभी भी दमन और पुलिस आतंक जारी है. बहुत से यूनियन नेताओं और मजदूरों को मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है. राज्य कमेटी ने पूरी घटना की न्यायायिक जांच की मांग की है.

जबकि सरकार 1982 का वर्ष उत्पादकता वर्ष के रूप में मना रही है, विनोद और विमल मिलों को अभी तक पूरी तरह से नहीं खोला गया है और हजारों मजदूरों को बेरोजगार रखा जा रहा है.

राज्य कमेटी ने मध्य प्रदेश सरकार की न्यूनतम वेतन पर जारी अधिसूचना की जो कि देश में सबसे कम है यहां तक कि बिहार, म० प्र० और राजस्थान से भी. खेत मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन को लागू नहीं किया जा रहा है.

राज्य कमेटी ने मध्य प्रदेश श्रम मंत्रालय के कार्यालयों की निन्दा की है, जोकि एक इंटकी नेता के अधीन है, और सीटू को अपना मुख्य निशाना बनाते हुए सभी गैर-इंटक यूनियनों को समाप्त करने तथा गैर-इंटक यूनियनों के विवादों में हस्क्षेप न करने की नीति अपना रहे हैं.

राज्य कमेटी ने पत्रकारों के संघर्ष का समर्थन करने के साथ बिहार प्रेस विधेयक की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पास किया तथा इसके वापसी की मांग की. एक अन्य प्रस्ताव में कमेटी ने केन्द्र सरकार से बम्बई के कपड़ा मिलों की हड़ताल का अविलंब तय कराने की मांग की.

कमेटी ने 1 सितम्बर के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और एकजुटता दिवस को सफल बनाने की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया तथा 4 अक्तूबर के दिल्ली शांति मार्च में शामिल होने के लिये बड़ी संख्या में मजदूरों को हरकत में लाने के लिये सीटू यूनियनों का आह्वान किया.

बी० आई० वर्कर्स यूनियन की वार्षिक आम सभा

बंगाल इम्युनिटी वर्कस यूनियन की जनकपुर इमाई की चौथी वार्षिक आम सभा 4 सितम्बर को जनकपुर में डी० सी० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. केन्द्रीय यूनियन, कलकत्ता के महासचिव डी० बसु ने सदस्यों के समक्ष विचाराधीन मांगपत्र की चर्चा की. सम्मेलन ने कंपनी का, जिसके प्रशासन को केन्द्रीय सरकार पहले ही अपने हाथ में ले चुकी है, राष्ट्रीय-करण करने, जूट और टेक्सटाइल मजदूरों की मांगों को पूरा करने तथा एफ० एम० आर० ए० आई० के जोनल सचिव आर० हांडा की बहाली की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किये. 5 सितम्बर को एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीटू व एटक तथा अन्य विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन ने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास किये. सम्मेलन ने एन० एस० ए० एस्मा व चारों काले विधेयकों तथा बिहार प्रेस विधेयक को खतम करने की मांग की. इसने सरकार की बहुराष्ट्रीय समर्थन नीतियों तथा आई० एम० एफ० कर्जों की निन्दा की. सम्मेलन ने अमरीकी साम्राज्यों द्वारा की जा रही नाभिकीय युद्ध की तैयारियों की निन्दा की और सभी मजदूरों से युद्ध योजनाओं के खिलाफ शांति संघर्ष में शामिल होने की अपील की. सम्मेलन ने पी० एल० ओ० के खिलाफ अमरीका समर्थित इजरायली हमले की निन्दा की तथा पी० एल० ओ० और लेबनानी जनता के जीवन और मौत के संघर्षों को अपने पूरे-पूरे समर्थन का इजहार किया,

इस्पात मजदूरों का घरना

जुलाई में संपन्न इस्पात मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन के निर्णयों का अनुपालन करते हुए हिन्दुस्तान इम्प्लाईज यूनियन ने मांगपत्र पर वार्ता करने की मांग करते हुए 30 एवं 31 अगस्त को इस्पात भवन, भिलाई, के समक्ष दिन भर का घरना आयोजित किया. पुराना समझौता 31 अगस्त को समाप्त हो रहा था. घरने में सीटू और एटक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. 31 अगस्त को दोपहर बाद घटना-स्थल पर एक आम सभा हुई जिसे सीटू के पी० के० मोइत्रा तथा एटक के एम० सी० सोनी ने सम्बोधित किया.

बिहार

नगरपालिका मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

पटना नगरमहापालिका के 7000 मजदूरों ने अपनी 33 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिये 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी. उनकी मांगों में दैनिक वेतन मजदूरों को नियमित करना तथा अन्य मजदूरों के समान वेतन देना, पेंशन योजना, देय हो चुके महंगाई भत्ते की चार किस्तों की अदायगी तथा चतुर्थ वेतन सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करना आदि शामिल है.

मजदूरों ने संघर्ष का समर्थन करते हुए बिहार राज्य सीटू के उपाध्यक्ष हरी कृष्ण तथा महासचिव चण्डी प्रसाद ने एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से सरकार से नगरपालिका मजदूरों की जायज मांगें स्वीकार करने की मांग की. उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाने के लिये सरकार की तीव्र आलोचना की, जिसने न केवल मजदूरों को बल्कि सारी जनता को कठिनाइयों में डाल दिया है. ट्रेड यूनियनों ने निगम के संघर्षरत मजदूरों को पूरा-पूरा समर्थन देने तथा मांगें पूरी करने के लिये सरकार पर दबाव डालने की अपील की है.

उत्तर प्रदेश

राज्य कमेटी आंदोलन को तेज करेगी

राज्य कमेटी ने 14-15 अगस्त को कानपुर में संपन्न अपनी बैठक में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का पालन करते हुए छेड़े गये दमन की खिलाफत करने के लिये चौतरफा आंदोलन तेज करने का निर्णय किया. राज्य कमेटी ने उ० प्र० सरकार द्वारा विवादों में हस्तक्षेप करने अथवा उन्हें मध्यस्थता के लिये सौंपने से इंकार करने तथा बहुत सी यूनियनों को पंजीकृत करने से इंकार करने के खिलाफ उ० प्र० के सभी जिलों में प्रदर्शनों, धरनों, जुलूसों तथा रैलियों के आयोजन का भी निर्णय लिया. कानपुर कार्यालय पर विशेष रूप से लगातार कार्रवाई जारी रखी जायेगी. सीटू गैर-इंटक यूनियनों को भी हरकत में लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा जो कि स्वयं भी सरकार द्वारा इंटक को संरक्षण दिये जाने से पीड़ित है. राज्य कमेटी ने असंगठित मजदूरों के लिये 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग के लिये आंदोलन तेज करने का भी निर्णय लिया. कमेटी ने मजदूरों के ट्रेड यूनिय एवं हड़ताल करने के अधिकार को छीनने के इरादे से लाये गये चारों विधेयकों के खिलाफ तथा एन० एस० ए० और एस्मा को रद्द करने के लिये अन्य यूनियनों के साथ मिलकर लगातार संघर्ष चलाने का निणय लिया. इसने उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का भी निणय लिया. राज्य में बहुत से यूनिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया है. केवल कानपुर में ही जूट में 33, टेक्सटाइल में 40, रेयन में 12, बिस्कुट फैक्ट्री में 10, तथा इंजीनियरिंग एवं अन्य उद्योगों में लगभग 100 नेताओं और मजदूरों को उत्पीड़ित किया गया है.

राज्य कमेटी ने बिहार प्रेस विधेयक की निन्दा की तथा इसके खिलाफ पत्रकारों के संघर्ष को पूरा-पूरा समर्थन देने के लिये मजदूरों का आह्वान किया. बम्बई के संघर्षरत कपड़ा मजदूरों के लिये कोष एकत्रित करने का निर्णय भी लिया गया.

राज्य कमेटी ने 1 सितंबर के शांति और एकजुटता दिवस तथा 4 अक्तूबर के शांति मार्च के लिये ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को हरकत में लाने का निर्णय लिया. इसने पूरे राज्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक युद्ध-विरोधी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया.

जे० के० जूट मजदूरों की हड़ताल

सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के महासचिव दौलतराम ने 26 अगस्त को जारी प्रेस वक्तव्य में जे० के० जूट मिल मजदूरों की 90 दिन पुरानी हड़ताल पर रोक लगाने वाले उ० प्र० सरकार ने अध्यादेश की निन्दा करते हुए कहा है कि इस अध्यादेश ने मजदूरों के न्यायोचित संघर्षों को खतम करने के लिये इजारेदारों-सिहानियाओं—के साथ सरकार की सांठ-गांठ को और भी प्रमाणित कर दिया है. यह दूसरा मौका है जबकि उ० प्र० सरकार ने हड़ताल को गैर-कानूनी करार देने के लिये अध्यादेश जारी किया है और खुल्लम-खुल्ला सिहानियों का समर्थन कर रही है. पिछली बार यह अप्रैल के महीने में किया गया था जबकि मजदूरों ने 7 मई को सरकार ने आश्वासन पर अपनी 83 दिन पुरानी हड़ताल वापस ले ली थी. परंतु सरकार ने 20%बोनस की उनकी मांग पर वार्ता करने के बजाय अपने गुण्डों की मदद से मजदूरों पर हमले करने में प्रशासन को मदद करने के लिये अपनी मशीनरी को खुला छोड़ दिया. 27 नेता और कार्यकर्त्ता उत्पीड़ित किये जा चुके हैं. दौलतराम ने संघर्षरत जे० के० जूट के मजदूरों का समर्थन करने के लिये मजदूरों के सभी हिस्सों का आह्वान किया है.

तमिलनाडु

अभियान और निर्णय

सीटू की तमिलनाडु राज्य कमेटी की बैठक 13-15 अगस्त को तूतीकोरिन में के० रमनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. महासचिव आर० उमानाथ ने हाल के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के घटनाक्रमों का विवरण पेश किया. कमेटी ने सरकार की लगातार बढ़ रही मजदूर विरोधी नीतियों पर जो कि विशेष रूप से सीटू को अलग-थलग करने और उसे हमले का निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, विचार विमर्श किया. संघर्षों और दिन प्रति दिन की ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है. तमिलनाडु वाटर एण्ड ड्रेनेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर ने कर्मचारियों को सीटू युनियन का सदस्य न बनने, क्योंकि यह एक राजनीतिक पार्टी की ट्रेड यूनियन है, की चेतावनी देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. एक तरफ सीटू पर इस तरह की पाबन्दी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ राज्य के श्रम मंत्री स्वयं बोर्ड की ए० डी० एम० के० यूनियन द्वारा आयोजित समारोह में हिस्सा लेते हैं.

कमेटी ने राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 13 सितम्बर को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है.

कमेटी ने "सबको बोनस" का अभियान चलाने तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मद्रास, कोयम्बटूर, मदुराई और पांडिचेरी में बोनस सम्मेलन करने का निर्णय भी लिया.

कामगार महिलाएं

कमेटी ने महिला कामगारों को ट्रेड युनियन संघर्षों में लामबन्द करने तथा उनकी खास समस्याओं का समर्थन करने के लिए, मदुराई, मद्रास, कोयम्बटूर तथा सलेम में कामगार महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया. कन्याकुमारी में इस तरह का एक सम्मेलन पहले ही किया जा चुका है.

हैंडलूम

कमेटी ने हरकारिता मजदूरों को हैंडलूम एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए मजदूरों को हरकत में लाने के लिए एटक

और डी० एम० के० युनियनों के साथ जिलास्तरीय सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया. मास्टर बुनकरों ने इस निर्णय के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट से पहले ही स्थगन-आदेश हासिल कर लिया है.

शहीद-कोष

कमेटी ने सभी युनियनों को आदेश दिया है कि वे शहीदों के परिवारों तथा 11 सितम्बर के मयुरम समारोह में गम्भीर रूप से घायल मजदूरों को देने के लिए धन एकत्रित करने का काम 31 अगस्त तक पूरा कर लें. कमेटी ने अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए जा रहे युद्ध के खतरे, लेबनान पर इजरायली हमले, काले कानूनों तथा बंदी, छंटनी और कीमत वृद्धि के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किए.

इंजीनियरिंग मजदूरों का सम्मेलन

कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियरिंग एण्ड मेकेनिकल वर्कस युनियन के तत्वावधान में इंजीनियरिंग मजदूरों का एक सम्मेलन 25 अगस्त को कोयम्बटूर में सम्पन्न हुआ. आर० वेंगुडू ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. महासचिव यु० के० वेलिगिरी और एम० भास्करन ने अपनी रिपोर्ट में इंजीनियरिंग मजदूरों की समस्याओं की विस्तार से चर्चा की. ले आफ छंटनी और उत्पीड़न के अन्य तरीके काफी बढ़ गये हैं. सम्मेलन ने मजदूरों के हितों की रक्षा करने तथा इंजीनियरिंग मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा तय की गई मांगों के लिए एकजुट आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया. पश्चिम बंगाल के यातायात मंत्री तथा टेक्सटाइल वर्कस युनियन के नेता राबिन मुखर्जी, खेत मजदूर युनियन, डी० वाई० एफ. आई० तथा अन्य युनियनों ने सम्मेलन का अभिनंदन किया. मजदूरों ने उस दिन बिल्ले लगाए तथा गेट मीटिंगें कीं और दोपहर के बाद विशाल जुलूस में हिस्सा लेने के लिए एक घण्टे के लिए अपना काम बन्द कर दिया. जुलूस में लगभग 5000 मजदूरों ने हिस्सा लिया जो बाद में जन सभा में परिवर्तित हो गया. सभा को अन्य लोगों के अतिरिक्त राबिन मुखर्जी, के० रमनी, वेंगुडू तथा वेलिगिरि ने सम्बोधित किया.

इस्पात मजदूरों का प्रदर्शन

सलेम स्टील प्लांट के मजदूरों ने अपनी सीटू युनियन के नेतृत्व में 25 से 31 अगस्त तक विरोध सप्ताह मनाया. यह विरोध दिवस नये मांग पत्र पर वार्ता करने तथा बी० पी० ई० के निर्देशों के खिलाफ बोकारो में सम्पन्न इस्पात मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन के निर्णयानुसार मनाया गया. 31 अगस्त को कारखाने के गेट पर विशाल जन सभा और प्रदर्शन का आयोजन किया गया.

आंध्र प्रदेश

चीनी मिलों के अधिग्रहण के लिए धरना

400 गन्ना उत्पादकों तथा 650 मजदूरों ने आंध्र प्रदेश में किरलंपुडी सुगर मिल के प्रशासनिक भवन के समक्ष लगातार 15 दिनों तक धरना दिया. मजदूरों के प्रति अपनी दमनात्मक नीतियों के अलावा मिल के प्रशासन ने पंजीकृत गन्ना उत्पादकों को कम कीमत दी और लगभग 40 लाख की धनराशि को काफी दिनों तक बकाया रखा, उन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखा तथा मजदूरों को दिए गये सरकार के वेतन निर्णय को लागू नहीं किया. प्रशासन की मजदूर-विरोधी तथा गलत नीतियों के कारण दिन प्रति दिन 600 से 800 टन गन्ने की पेराई कर रही थी जबकि इसकी क्षमता 13000 टन गन्ना प्रतिदिन पेरने की है. प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मिल को बेच देने की कोशिश की. परन्तु मजदूरों ने कड़ी निगरानी रखी और प्रशासन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया. सरकार ने मिल मालिकों को गुप्त रूप से समर्थन दिया और मिलों का अधिग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं किया जब कि 1977 में ही सरकार ने ऐसा करने का अपना निर्णय घोषित किया था. सीटू की आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष जी० एस० बालाजी दास ने एक बयान में सरकार की नीतियों की निन्दा की और तुरन्त मिलों को अधिग्रहण करने की मांग की. धरने के दौरान प्रशासन ने तालाबन्दी घोषित कर दी और बचने की कोशिश की. परन्तु गन्ना उत्पादकों और मजदूरों के समूह ने सरकार को मिल के मुख्य प्रशासक को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर कर दिया. विधान सभा में चीनी मंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मिलों का अधिग्रहण करने जा रही है और उसने आवश्यक कार्यवाही के लिए केन्द्र सरकार को निवेदन किया है.

लारी मजदूर महासंघ का गठन करेंगे

आंध्र प्रदेश की लारी वर्कर्स यूनितन ने अपना राज्य व्यापी फेडरेशन गठित करने तथा उसे आल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया. यह निर्णय 15 अगस्त को नेल्लोर में सम्पन्न लारी मजदूरों के एक सम्मेलन में लिया गया. आंध्र प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष तथा सीटू राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष जी० एस० बालाजी दास ने झण्डारोहण किया तथा सीटू की राज्य कमेटी के महासचिव एन० प्रसाद राव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया.

सम्मेलन में 31 यूनियनों के 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 22 यूनियनें सीटू से सम्बद्ध थीं. सम्मेलन ने विशेष रूप से वेथम तेरला, यामीगनपुर, नान्दुयाला, तथा अदोनी आदि जगहों पर मजदूरों तथा यूनियनों पर बढ़ रहे मालिकों के हमलों पर तथा नेल्लोर, कुनुंल, काकीनाडा, साठीपल्ली, अमु-

दालावालासु, अमलपुरम, पिठापुरम, खम्मम, मिलवारम, कांकीपाडु, मंगलगिरि, चिहलालुरिपेट, नरसारावपेट, सिंगारहाकोंडा, गुडूर, नायुडूपेटा, केन्दुकुरा,गिडालुरु, नन्दीकोटकुरु, नायुयाला, गुण्टाकल्लू, द्रोनाएलम तथा अन्य जगहों पर अधिक वेतन और भत्तों के लिए लारी मजदूरों की जोरदार सफल हड़ताल पर विचार विमर्श किया. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करने मंहगाई भत्ते की अदायगी, दैनिक भत्तों में वृद्धि आदि की मांगों के लिए प्रस्ताव पास किए गये. सम्मेलन में 1 सितम्बर के शान्ति और एकजुटता कार्यक्रम में भी शामिल होने का निर्णय लिया.

एम० मलाकोंडा रेड्डी तथा के० वेंकटेश्वरलु क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री चुने गये. सम्मेलन में अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 21अक्टूबर को पूरे राज्य में प्रदर्शन और आम सभाएं करने का निर्णय लिया. यह सम्मेलन विशाल जनसभा के साथ सम्पन्न हुआ.

अण्डमान निकोबार द्वीप जंगल और प्लांटेशन मजदूर भख हड़ताल पर

अण्डमान जैसे छोटे से द्वीप पर जंगल और प्लांटेशन विकास निगम के मजदूरों ने 16 अगस्त से क्रमिक अशन शुरु कर दिया. इस आंदोलन का आह्वान अण्डमान निकोबार गवर्नमेंट इम्प्लाईज एण्ड वर्कर्स फेडरेशन से सम्बद्ध वनविकास कर्मचारी संघ के द्वारा बहुत दिनों से विचाराधीन अपनी मांगों को हासिल करने के लिए किया गया था. कर्मचारियों ने भूखहड़ताल से पूर्व 14 अगस्त को अपनी मांगों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला. जुलूस में पहली बार काफी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया. सरकार का मजदूर विरोधी दृष्टिकोण उस समय खुलकर सामने आ गया जब कि श्रम आयुक्त ने युनियन के महासचिव को पोर्ट ब्लेयर बुलाया और उन्हें कोई भी आंदोलनात्मक कारंवाई न करने का आदेश दिया. फिर भी महामंत्री ने साफ साफ कह दिया कि चूंकि सरकार मजदूरों की मांगों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है और आंदोलन की शुरुवात यथोचित सूचना देने के बाद की गई है अत: अब आंदोलन तभी वापस हो सकता है जब कि सरकार मांगों को पूरा करे. ।चूंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला अत: संघ ने 23 अगस्त से आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया है. □

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केन्द्र	1982 अप्रैल	मई	जून
बिहार			
जमशेदपुर	444	440	448
झारिया	442	441	440
कोडर्मा	498	492	501
मोंघाइर	488	506	514
रोआमुंडी	447	456	457
गुजरात			
अहमदाबाद	461	466	472
भावनगर	452	455	467
हरियाणा			
यमुना नगर	498	495	505
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	537	520	503
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	477	478	473
भोपाल	491	490	496
ग्वालियर	476	479	490
इंदौर	505	505	514
महाराष्ट्र			
बंबई	473	479	488
नागपुर	476	478	482
शोलापुर	492	493	500
पंजाब			
अमृतसर	480	477	472
राजस्थान			
अजमेर	483	482	493
जयपुर	496	495	511
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	446	446	456
सहारनपुर	475	474	480
वाराणसी	508	501	510
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	465	462	471
कलकत्ता	422	430	437
दार्जीलिंग	381	386	389
हावड़ा	408	411	420
जलपाइगुरी	370	371	377
रानीगंज	450	452	457
दिल्ली	493	495	500
भारत	459	462	470

संक्षिप्त समाचार

बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार के मजदूरों ने 9 अगस्त को अपनी विभिन्न मांगों के लिये संघर्ष की तैयारी करने के लिए गेट मीटिंग का आयोजन किया. दिल्ली राज्य सीटू के महासचिव एवं संसद सदस्य सुशील भट्टाचार्या ने मजदूरों को सम्बोधित किया.

\+ + +

आई० डी० पी० एल०, रिसीकेश प्लांट के मजदूरों ने 8 अगस्त को आई० डी० पी० एल० कामगार युनियन (सीटू) के तत्वावधान में गेट मीटिंग की जिसे सुशील भट्टाचार्य, जो कि युनियन के अध्यक्ष भी हैं, ने तथा अन्य लोगों ने सम्बोधित किया.

\+ + +

सहारनपुर में कपड़ा मिल पर 7 अगस्त को एक संयुक्त गेट मीटिंग हुई जिसमें सीटू, एटक, एच०एम०एस०, बी० एम०एस०, ने हिस्सा लिया. सुशील भट्टाचार्जी और गुलाब सिंह ने सीटू की तरफ से सभा को सम्बोधित किया. सभा का आयोजन मजदूरों की मांगों को हल कराने के लिए संयुक्त संघर्ष हेतु उन्हें हरकत में लाने के लिए किया गया था.

\+ + +

निर्माण मजदूर को आर्डीनेशन कमेटी, पूर्वी क्षेत्र, की बैठक 1 अगस्त को सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के कलकत्ता स्थित कार्यालय में हुई जिसमें सेवा सुरक्षा तथा नेशनल वेज बोर्ड सम्बन्धी उनकी मांगों को हासिल करने के लिए अभियान आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया. बैठक में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम से लगभग 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में विभिन्न कार्यस्थलों पर सम्मेलन करना एवं केन्द्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन देना सामिल है. बैठक में मेट्रो रेलवे मजदूरों की कार्यगत परिस्थितियों को सुधारने के लिए एकजुट आन्दोलन की योजना तैयार करने के लिए एक अलग सम्मेलन करने का निर्णय भी लिया गया.

\+ + +

इलाहाबाद में 12 जुलाई को सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिये सीटू एवं एटक द्वारा संयुक्त रूप से श्रम कार्यालय पर धरने का आयोजन किया गया. इसके बाद न्यूज पेपर इम्प्लाईज युनियन की तरफ से सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा मजदूरों के 7 सूत्री मांगपत्र के लिये एकजुट आन्दोलन हेतु मजदूरों को आन्दोलित करने के लिये माया प्रेस के गेट पर एक आम सभा का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता उ० प्र० किसान सभा के संयुक्त सचिव अम्बिका प्रसाद मिश्र ने की.

फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन्स आफ इण्डिया (एफ० एम० आर० ए० आई०) ने 29 और 30 जुलाई को मद्रास में सम्पन्न अपनी कार्यकारिणी की बैठक में श्रम विभागों पर धरनों, रैलियों व प्रदर्शनों के साथ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया जिसकी परिणति एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में होगी. वे दवा उद्योग में त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं जिसे केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता संघों के दबाव के कारण दो बैठकों के बाद स्थगित कर दिया है. इसी बीच अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जानवीथ के प्रशासन ने फेडरेशन के जोनल सचिव आर० हांडा की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया है. उत्तरी क्षेत्र की सम्बद्ध इकाइयों के लगभग 500 सदस्यों ने 2 सितम्बर को हांडा की पुनर्बहाली और त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की मांग करते हुये नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन पर दिन भर धरना दिया.

\+ + +

उत्तर प्रदेश खदान विकास निगम के अधिकारियों ने बिल्ली गांव के हरिजन किसानों की 200 बीघा जमीन बिना कोई मुआवजा दिये हड़प ली. काफी संघर्ष करने के बाद प्रभावित लोगों को निगम में भर्ती करने का एक समझौता सम्पन्न हुआ. परन्तु प्रशासन ने समझौते का उल्लंघन करते हुये बाहर से भर्ती के लिये 11 अप्रेल को ओबरा स्थित अपने कार्यालय में साक्षात्कार के लिये बुलाया. सीटू ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें इंटक को छोड़कर बाकी सभी युनियनों के मजदूरों और किसानों ने हिस्सा लिया. पुलिस और गुण्डे प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े तथा बहुतों को बुरी तरह घायल कर दिया. कई मजदूरों के खिलाफ डकैती के आरोप लगाए गये. एक मजदूर को बरखास्त, 8 को निलम्बित तथा 4 को स्थानान्तरित कर दिया गया. मजदूरों ने 17 अप्रेल को 500 की विशाल संख्या में प्रदर्शन किया और खदान के कामकाज को ठप्प कर दिया. 28 मई और 6 जून को सभाएं की गई तथा 10 जून से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया. संघर्ष को नेतृत्व दे रही माइन वर्कर्स युनियन (सीटू) ने सघर्ष का अगला कार्यक्रम तय कर लिया है.

\+ + +

सीटू कार्यकर्त्ता आर० के० पाठक को गवर्नमेंण्ट ओपियम एण्ड अलकालायड वर्कस अण्डरटेकिंग, नीमुच, मध्य प्रदेश के इशारों पर पुलिस द्वारा गढ़े गये सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. सीटू युनियन का गठन होते ही प्रशासन ने मजदूरों पर दमन छेड़ दिया और पाठक को बर्खास्त कर दिया. प्रशासन ने पुलिस को कारखाने के अधीक्षक को कत्ल करने की धमकी देने का आरोप लगाने के लिए मजबूर कर दिया. परन्तु वे इसे सिद्ध नहीं कर सके अतः अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. उनकी बहाली के लिये संघर्ष जारी है.

अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित एक जुझारु कपड़ा मजदूरिनी बानो बहन को 8 मई को राजस्थान टैक्सटाइल मजदूर युनियन (सीटू) भवानी मंडी का अध्यक्ष चुना गया. बानो बहन को भूतपूर्व तोड़फोड़ करने वाले ग्रुप के द्वारा निकाल दिया गया था जिन्होंने युनियन का नेतृत्व हथियाने के लिए प्रशासन से सांठ गांठ कर रखी थी. परन्तु तीव्र आन्तरिक संघर्षों के द्वारा उन्हें अलग-थलग कर दिया गया और वे अध्यक्ष पद पर चुनीं गई. उन्हे नवनिर्वाचित सीटू की राज्य कमेटी का सदस्य भी चुना गया है.

\+ + +

श्री भवानी काटन मिल्स, अबोहर (पंजाब) के मजदूरों ने 28 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है. हड़ताल का आह्वान जबरदस्त बहुमत वाली सीटू युनियन के द्वारा 500 रुपया न्यूनतम वेतन, ठेका प्रथा की समाप्ति अनियमित और बदली मजदूरों को नियमित करने आदि मांगों के लिए किया गया था. सीटू कार्यकर्त्ता पुलिस के द्वारा पीटे जा रहे हैं. परन्तु युनियन ने हर दमन का सामना करते हुए 8 जुलाई को श्रमिक विरोधी काला विधेयक दिवस के दिन 4000 मजदूरों का विशाल जुलूस निकाला.

\+ + +

पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्टाफ फेडरेशन ने 16 जुलाई को दिल्ली में सम्पन्न एक सम्मेलन में अपनी दिल्ली एरिया कमेटी का गठन किया. सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन ने सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों तथा काले विधेयकों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए. लाल सिंह, और एम० एस० अरोरा क्रमश: अध्यक्ष और सचिव चुने गए.

\+ + +

सीटू के उम्मीदवार राज शर्मा और सच्चिदानन्द डुडियाल 16 अगस्त को सम्पन्न वार्षिक चुनाव में प्रेस वर्कर्स युनियन, देहरादून के अध्यक्ष और महामंत्री चुने गये. सीटू उम्मीदवारों की विजय ने मजदूरों पर गहरा प्रभाव डाला. आर्मी प्रेस के प्रशासन को बहुत दिनों से विचाराधीन दैनिक वेतन-भोगी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने मासिक वेतन में कुछ बढ़ोत्तरी करने तथा हड़ताल के समय का पूरा वेतन देना आदि मजदूरों की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया.

× × ×

सीटू की दिल्ली जिला कमेटी के आह्वान पर 24 अगस्त को लगभग 1000 मजदूरों ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में जुलूस निकाला वे 500 रुपये न्यूनतम वेतन, बन्दी, तालाबन्दी और छंटनी को रोकने, ठेका प्रथा के खात्में, एन०एस०ए०, एस्मा तथा अन्य श्रमिक विरोधी कानूनों को खतम करने आदि मजदूरों की बहुत सी मांगों से सम्बन्धित नारे लगा रहे थे. प्रदर्श का नेतृत्व सीटू की दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव पूरनचन्द और एस० वी भारद्वाज ने किया.

× × ×

सीटू के तीन और एटक के दो लाल झण्डा उम्मीदवारों ने 18 अगस्त को अरविन्द ट्रेक्सटाइल मिल, अहमदाबाद में ज्वाइंट मैनेजमैंट काउंसिल का चुनाव जीत लिया. बी आइ० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा संरक्षित टैक्सटाइल लेबर यूनियन की बुरी तरह से हार हुई. सीटू सम्बन्ध महा गुजरात मिल मजदूर युनियन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन ने दमन शुरू कर दिया. इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा और प्रशासन समर्थित टी० एल० ए० के उम्मीदवार बुरी तरह से पराजित कर दिए गये. सीटू युनियन ने मजदूरों की मांगों के लिए 14 सितम्बर को अहमदाबाद के मिल मजदूरों का एक सम्मेलन बुलाया है.

× × ×

कामर्शियल स्प्रिजेंटेटिव्स युनियन गौहाटी, ने का० प्रणय पात्र तथा का०जे०चक्रवर्ती की सेवाओं को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठान स्मिथ स्तानीस्ट्रीट एण्ड कं०लि० और प्रिमियर मेडिकल सप्लाईज के प्रशासन के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया है. प्रशासन ने इनकी सेवाओ को बिना कोई कारण बताए ही समाप्त कर दिया है. प्रिमियर मेडिकल सप्लाईज के कर्मचारियों ने 12 अगस्त से नियमानुसार कार्य करने का निर्णय लिया है.

× × ×

आसाम राज्य मेकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कर्स युनियन का पांचवा वार्षिक सम्मेलन दि० 5 से 7 अगस्त को सिलचर में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन ने वर्क चार्ज और मस्टर रोल मजदूरों को नियमित कराने के लिए, जिसे आसाम सरकार ने नीति के रूप में स्वीकार किया था परन्तु कभी भी लागू नहीं किया, संघर्ष शुरू करने का निर्णय किया. सम्मेलन ने एन० एस० ए० और एस्मा जैसे काले कानूनों का विरोध करने तथा पृथकतावादी और क्षेत्रीयतावादी ताकतों के खिलाफ मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करने का निर्णय भी लिया. का० हरिनाथ और का० अतुल हजारिका क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री चुने गये.

× × ×

युनाइटेड माइन्स मजदूर युनियन (सीटू) पुरनापानी शाखा के आहवान पर सैकड़ों मजदूरों किसानों एवं नवजवानों ने 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के नवगांव स्थित बी०डी०ओ० के कार्यालय पर संयुक्त प्रदर्शन किया. सम्मेलन का आयोजन बढ़ती कीमतों तथा सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए किया गया था. युनियन ने सितम्बर में जेल भरो आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है.

सीटू यूनियनों ने मद्रास और इसके उपनगरों में बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जीत हासिल की. सीटू यूनियनों के बढ़ते संघर्षों ने प्रशासन समर्थित सुधारवादी नेता आर० कुचलर के प्रभाव को अधिकांश यूनियनों में काफी कमक र दिया है. सीटू के वी० पी० चिन्तन ने अशोक लेलैण्ड, एम० आर० एफ० तथा बी० एण्ड सी० स्टाफ यूनियनों के चुनावों में आर० कुचेलर को पराजित कर दिया. इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी, इण्डिया ट्यूबको कम्पनी, स्टैंडर्ड मोटर्स आदि बहुत सी अन्य इकाइयों में सीटू समर्थित एटक प्रतिनिधियों ने कुचेलर को पराजित कर दिया.

× × ×

सीटू की हिस्सार जिला कमेटी का पहला सम्मलन 25 व 26 सितम्बर को हिस्सार में होना तय हुआ है. सम्मेलन भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर विचार करेगा तथा हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गये मजदूरों के बर्बर दमन के खिलाफ संघर्ष की रूप रेखा तय करेगा. निम्नांकित मांगों के साथ आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया जाएगा:— 500 रुपये न्यूनतम वेतन, ट्रेड्यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ, कमित वृद्धि के खिलाफ तथा उचित दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए. एन० एस० ए०, एस्मा, बिहार प्रेस विधेयक तथा अन्य श्रमिक विरोधी कानूनों की वापसी के लिए, ट्रड यूनियन संघर्षों में पुलिस का हस्तक्षेप वन्द कराने के लिए तथा उत्पीड़ित मजदूरों की पुनर्बहाली आदि.

× × ×

परवान्, हिमाचल प्रदेश के लघु उद्योग के मजदूरों ने 10 सितम्बर को एक घण्टे की सांकेतिक हड़ताल करने तथा उसके बाद 13 सितम्बर से क्रमिक अनशन करने का निर्णय लिया. आन्दोलन का आह्वान कंक्रीट पोल्स और पेपर कनवर्जन वर्कर्स यूनिन के द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में, जिन्हें जून में प्रशासन के समक्ष रखा गया था, किया गया था. परन्तु प्रशासन ने मांगों पर विचार विमर्श करके उन्हें तय करने के बजाय एक भी मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया तथा मजदूरों को गम्भीर परिणामों की धमकी देना शुरू कर दिया. मांगों में हिमाचल प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार न्यूनतम वेतन, नौकरियों को स्थाई करना, मंहगाई भत्ता, तथा महिलाओं के लिए समान वेतन आदि की मांगे शामिल हैं. यदि प्रशासन मांगे स्वीकार करने से इंकार करता है तो मजदूर आगे भी आन्दोलन जारी रखेंगे.

× × ×

थीन बांध परियोजना, पठानकोट के मजदूर पिछले एक महीने से क्रमिश अनशन कर रहे हैं. क्रमिक अनशन का आह्वान थीन डैम वर्कर्स यूनियन के द्वारा बहुत दिनों से विचाराधीन अपनी तीस सूची मांगों को तय करने के लिए किया गया था. प्रशासन के हर दमन का सामना करते हुए मजदूर प्रतिदिन प्रदर्शनों और जुलसों का आयोजन कर रहे हैं. यूनियन ने प्रशासन को मांगे पूर्ण न होने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल कर देने की चेतावनी दे दी है.

× × ×

हिन्दुस्तान स्टील इम्प्लाईज यूनियन (सीटू), भिलाई, ने अपने जोरदार संघर्ष से एच० एस० सी० एल० प्रशासन को कर्मचारियों को जलाने का कोयला देने के लिए, जिसे उन्होंने मनमाना तरीके से पिछले दो माह से बन्द कर रखा था, मजदूर कर दिया. 25 अगस्त को हस्तातरित एक समझौते में प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को कोक कार्ड देना स्वीकार किया है. युनियन ने ठेका प्रणाली को पूरी तरह से खतम करने तथा एच० एस० सी० एल० का पूरा पूरा काम निर्माण विभाग के मजदूरों के द्वारा कराए जाने की भी मांग की है.

4 अक्टूबर के दिल्ली शान्ति मार्च में हिस्सा लेने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अपील

इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य, महासचिव एटक, एम० के० पंधे सचिव सीटू, जे० एस० दारा अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अमर प्रसाद चक्रवर्ती, संसद सदस्य, महासचिव टी० यु० सी० सी०, सुशील भट्टाचार्या, उपाध्यक्ष यु० टी० यु० सी० ने 18 सितम्बर को निम्नांकित बयान जारी किया :—

हम संसद के शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन 4 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में संयुक्त रूप से विशाल शान्ति मार्च आयोजित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं.

जब कि सारी दुनिया के ऊपर नाभिकीय विश्व युद्ध का खतरा मण्डरा रहा है और साम्राज्यवादी खुल्लम खुल्ला ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मौके पर दुनिया के मजदूर वर्गों और जनता का फौरी कर्तव्य है कि वे युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष करें और साम्राजी साजिश को परास्त करें. भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राजी ताकतों की साजिशें अभी हाल में बढ़ गई हैं और डियागो गार्सिया में अमरीकी अड्डा हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा बन गया है. इसराइल की आक्रामक योजनाओं ने अमरीकी साम्राजियों की मदद से फिलिस्तीनी जनता के संघर्षों को खतरा पैदा कर दिया है. पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र की आपूर्ति ने इस क्षेत्र में पहले ही शान्ति को खतरा पैदा कर दिया है.

हम गम्भीरता पूर्वक ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों से भारी संख्या में शान्ति मार्च में शामिल होने की अपील करते हैं जिससे विश्व शान्ति की रक्षा के समर्थन में भारतीय मजदूर वर्ग की आवज को वुलन्द किया जा सके.

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र की तरफ से एम० के० पंधे द्वारा प्रकाशित तथा प्रोग्रेसित प्रिण्टर्स, 52, 53, इण्डस्ट्रियल शेड्स ओखला फेज I से मुद्रित.